



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अगस्त, 2020 ई0 (श्रावण 24, 1942 शक सम्वत्) [संख्या-28

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	₹0
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	475-519	3075
भाग 1-क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	353-357	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	223-239	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

नियोजन अनुभाग-2

उत्तराखण्ड लोक निजी सहभागिता (पीपीपी) संशोधित नीति-2019

04 अगस्त, 2020 ई0

संख्या 95/XXVI/दो(15)/2011-

विषय-सूची

1. प्रस्तावना एवं नीति के उद्देश्य-
2. लोक निजी सहभागिता की प्रक्रिया-
3. मूल सिद्धांत-
4. परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया-
5. अनुश्रवण, मूल्यांकन और निर्धारण तंत्र-
6. जोखिम निर्धारण तंत्र-
7. राज्य द्वारा सहयोग-
8. हितधारकों के अधिकारों का संरक्षण-
9. नीति की अवधि और समीक्षा-

संख्या 95/XXVI/दो(15)/2011-

1. प्रस्तावना एवं नीति के उद्देश्य**1.1 प्रस्तावना**

1.1.1 पर्वतीय क्षेत्र को विकसित करने के मुख्य उद्देश्य से दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना की गई।

वैश्वीकरण के इस युग में, सरकारों के लिये देश के सभी भागों में निवेश की पहुंच बढ़ा कर न केवल प्रतिस्पर्धी लाभ निर्मित करने बल्कि राष्ट्र/राज्य का समग्र व सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक संरचना में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 तक राष्ट्र की आर्थिकी को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आकार तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अवधारित किया गया है कि इस निवेश का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र से आना होगा। इसलिये निजी क्षेत्र को अवस्थापना विकास के साथ-साथ वर्तमान अवस्थापना में सेवा प्रदायगी के सुधार को प्रोत्साहित करने तथा सक्रिय रूप से प्रवृत्त करने की आवश्यकता है।

1.1.2 लोक निजी सहभागिता (पीपीपी), निजी क्षेत्र को लोक अवस्थापना विकास के लिये निवेश में प्रवृत्त करने हेतु, सर्वश्रेष्ठ साधनों में से एक है जिसके निम्नलिखित प्रयोजन हो सकते हैं :

क. सरकारी प्रयासों की सम्पूर्ति

ख. सरकार के उपलब्ध संसाधनों की अनुपूर्ति

ग. परियोजनाओं के निष्पादन और सेवा प्रदायगी में संचालनात्मक कुशलता और दक्षता लाना,

घ. सेवा प्रदायगी और मानक सेवा स्तरों में ग्राहकोन्मुखी दृष्टिकोण पैदा करना और

ड. अंततः इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करना।

1.1.3 राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं० 538/XXVI/2(15)/2011 द्वारा वर्ष 2012 में "लोक निजी सहभागिता नीति" लागू की गयी थी। वर्तमान परिदृश्य में आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/गाईडलाइन तथा बाजार में विकसित नये प्रचलों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रख्यापित नीति में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गयी है, जिस कम में परियोजनाओं में संस्थागत, ढांचागत विकास की आवश्यकता तथा संरचनात्मक प्रणाली को अद्यतन किया जाना नई नीति में प्रस्तावित है। इस लोक निजी सहभागिता नीति में सर्वप्रथम लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सुस्पष्ट सहायता की घोषणा और उनके विनियमन तथा राजकोषीय अनुशासन सुदृढीकरण में नियामक की स्थिति पर भी विचार किया गया है।

लोक निजी सहभागिता का पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार लोक निजी सहभागिता परीक्षण हेतु, परियोजना लागत के सम्बन्ध में एक निश्चित आकार से अधिक की सभी अवस्थापना परियोजनाओं पर लागू किए जाने हेतु दिशानिर्देश जारी करेंगी। यदि लोक निजी सहभागिता परीक्षण से संकेत मिलता है कि परियोजना लोक निजी सहभागिता के माध्यम से सरकार और समस्त हितधारकों के लिए लाभदायक होगी, तब इसको लोक निजी सहभागिता परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा। लोक निजी सहभागिता परीक्षण में लोक निजी सहभागिता के माध्यम से सरकारी धन के अलाभकारी मूल्य द्वारा लोक निजी सहभागिता की असंभावना का संकेत मिलने की स्थिति में ही इस पर पूर्ण सरकारी वित्तपोषण के अधीन विचार किया जाएगा।

1.2 लोक निजी सहभागिता की परिभाषा

1.2.1 पीपीपी, बुनियादी ढांचे के विकास या सेवा प्रदायगी के लिये सार्वजनिक संस्था और निजी भागीदार के मध्य एक व्यवस्था है। पारम्परिक निर्माण सम्बन्धित अनुबन्धों के अधीन निजी क्षेत्र केवल डिजाइन और निर्माण जोखिम को वहन करता है, जबकि पीपीपी के अधीन, सार्वजनिक इकाई और निजी भागीदार के बीच जोखिम सांझाकरण तंत्र के आधार पर वित्त पोषण, मॉग और संचालन से सम्बन्धित अन्य जोखिमों को वहन करने की सम्भावनायें होती हैं।

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पीपीपी की परिभाषा को केवल आधार भूत संरचना/सम्बन्धित सेवाओं के प्राविधानों तक सीमित नहीं किया है, बल्कि इस क्षेत्र की परिधि और प्रयोज्यता में विस्तार किया है। यह पीपीपी को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

यह निजी लोक निजी सहभागिता को "एक पक्ष के रूप में सरकार अथवा सांविधिक संस्था अथवा सरकारी स्वामित्वाधीन संस्था और दूसरे पक्ष के रूप में निजी क्षेत्र की संस्था के बीच, एक सुनिश्चित समयावधि के लिए निजी क्षेत्र सत्ता द्वारा किए जाने वाले निवेश तथा/अथवा प्रबंधन के माध्यम से, लोक लाभ के लिए लोक अवस्थापना संपत्तियों तथा/अथवा सम्बन्धित सेवाओं के प्राविधान हेतु एक अनुबन्ध आधारित व्यवस्था, जहां निजी क्षेत्र के साथ भारी जोखिम हिस्सेदारी है तथा निजी क्षेत्र निष्पादन से सम्बद्ध भुगतान प्राप्त करता है, जो सुनिश्चित, पूर्व-निर्धारित और मापनीय निष्पादन मानकों के समनुरूप (अथवा निदेशचिन्हित) है" के रूप में परिभाषित किया गया है।

1.2.2. सरकारी इकाई का तात्पर्य:

- क. सरकारी विभाग एवं निदेशालय।
- ख. सरकारी प्रायोजित बोर्ड, समितियां तथा अन्य स्वायत्त निकाय।
- ग. सरकारी प्रायोजित शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन संस्थान।
- घ. शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतें।
- ड. सरकारी स्वामित्वाधीन कम्पनियां।

निजी क्षेत्र की संस्था का तात्पर्य, ऐसी संस्था है जिसका 51 प्रतिशत अथवा अधिक अंशदानकृत और प्रदत्त इक्विटी एक निजी संस्था द्वारा स्वाधिकृत तथा/अथवा नियंत्रित है, जिसमें निजी रूप से स्वाधिकृत/प्रायोजित समितियां, अलाभकारी संगठन भी शामिल होंगे।

1.3 लोक निजी सहभागिता की आवश्यक शर्तें:-

आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लोक निजी सहभागिता की परिभाषा के अनुसार पीपीपी को परिभाषित करने वाली आवश्यक शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

निजी क्षेत्र की इकाई के साथ व्यवस्था	निजी भागीदार द्वारा उपयोगकर्ताओं को संविदात्मक व्यवस्था के तहत सम्पत्ति और/या सेवा प्रदान की जायेगी। यह व्यवस्था निजी क्षेत्र को सार्वजनिक सम्पत्ति प्रदान करने और सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाती है। जोखिमों और प्रतिफल के बंटवारे के लिये एक तंत्र तैयार करती है। ऐसी इकाई, जिसके पास गैर-सरकारी स्वामित्व हो, अर्थात् 51 प्रतिशत या उससे अधिक गैर सरकारी स्वामित्व हो, को एक निजी क्षेत्र की इकाई के रूप में माना जा सकता है।
सार्वजनिक लाभ के लिये सार्वजनिक सम्पत्ति या सेवा का प्राविधान	पीपीपी में उन्ही सुविधाओं/सेवाओं को निजी भागीदार को हस्तान्तरित किया जाता है जो आमतौर पर सरकार द्वारा लोगों को एक संप्रभु कार्य के रूप में प्रदान की जाती है। इसे और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है:- "सार्वजनिक सेवायें" वह सेवायें हैं जिन्हें राज्य अपने नागरिकों को प्रदान करने के लिये बाध्य है या जहां परम्परागत रूप से राज्य अपने नागरिकों को सेवायें प्रदान करता आ रहा है। "सार्वजनिक सम्पत्ति" वह सम्पत्ति, जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवा के वितरण के लिये स्थाई रूप से जुड़ा हुआ है, या वे सम्पत्ति जो सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिये संप्रभु सम्पत्ति का उपयोग अथवा एकीकृत करती है।

निजी भागीदार द्वारा किये गये और या प्रबंधन द्वारा किये जा रहे निवेश	निजी भागीदार द्वारा वित्तीय निवेश पीपीपी के लिये एक आवश्यक शर्त नहीं हो सकती है। जहां एक निजी निवेश के बिना केवल निजी क्षेत्र की क्षमताओं का उपयोग सेवाओं की बेहतर प्रदायगी के लिये किया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था को पी0पी0पी0 के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
समयावधि	यह व्यवस्था निर्दिष्ट समयावधि के लिये होनी चाहिये। पीपीपी की कोई भी व्यवस्था हमेशा के लिये नहीं हो सकती है। यह भागीदारों के मध्य ऐसी व्यवस्था है, जो निर्दिष्ट समयावधि के अन्त में स्वतः समाप्त हो जाती है, जब तक की अनुबन्ध की शर्त के अनुसार पारस्परिक रूप से विस्तारित न हो।
जोखिम साझा करना	जोखिमों को साझा करना पीपीपी की प्रमुख विशेषता है। पी0पी0पी0 तत्र वह तत्र है जहां जोखिमों को या तो निजी भागीदार या सार्वजनिक संस्था, जो जोखिम के प्रबंधन और उसे कम करने के लिये सबसे उपयुक्त हो, को आवंटन किया जाता है। प्रत्येक पीपीपी व्यवस्था में एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिये भागीदारों (सार्वजनिक इकाई और पीपीपी व्यवस्था में प्रवेश करने वाले निजी भागीदार के बीच उल्लिखित हो) के मध्य जोखिमों का आवंटन निर्धारित समयावधि के लिये होगा।
प्रदर्शन आधारित भुगतान	पीपीपी व्यवस्था के अन्तर्गत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को भुगतान पर विचार किये जाने की व्यवस्था है। इन भुगतानों की मात्रा मुख्य रूप से किसी परिसम्पत्ति/सुविधाओं के प्रावधान पर निर्भर न होकर, सेवा वितरण और प्रदर्शन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।
प्रदर्शन मानकों की पुष्टि	सार्वजनिक कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट पूर्व निर्धारित मानकों के साथ-साथ मापने योग्य मानकों के अनुपालन एवं निजी भागीदार की सेवा प्रदायगी पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

सार्वजनिक संस्था और निजी भागीदार के बीच में, केवल उन व्यवस्थाओं को, जो कि उपरोक्त सभी आवश्यक शर्तों को सन्तुष्ट करते हो, को पीपीपी कहा जायेगा। प्रशासकीय विभाग प्रोजेक्ट को तैयार करते समय यह निर्णय करेगा कि प्रोजेक्ट उपरोक्त शर्तों के अनुरूप है तथा उसे पी0पी0पी0 में रखा जा सकता है।

1.4 प्रयोज्यता

1.4.1 यह नीति सरकार अथवा सरकारी संस्था, जैसा कि नीति के अंतर्गत पैरा-1.2.2 में परिभाषित है, द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए क्षेत्रों में लोक निजी सहभागिता के माध्यम से कार्यान्वित सामाजिक क्षेत्रों, प्राथमिक क्षेत्रों तथा सेवा उद्योगों समेत समस्त अवस्थापना परियोजनाओं पर लागू होगी। यह नीति 1.2.2 में परिभाषित राज्य सरकार की समस्त संस्थाओं पर लागू होगी।

1.5 नीति के उद्देश्य

1.5.1 इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :-

1. निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करना, ताकि :

क. वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु निजी क्षेत्र से अतिरिक्त पूंजी निवेश प्राप्त किया जा सके तथा सरकारी निधियों को वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य, किंतु सामाजिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण परियोजनाओं हेतु बेहतर आवंटन के लिए मुक्त रखा जा सके।

ख. निजी क्षेत्र की अभिनवता, लचीलापन, कारगर लागत, वैकल्पिक प्रबंधन और कार्यान्वयन कौशल संबंधी दक्षताओं का उपयोग किया जा सके।

- ग. उपभोक्ता और सर्वसाधारण को बेहतर गुणवत्ता की मूल्य वर्द्धित सेवाएं प्रदान और सुनिश्चित की जा सकें।
- घ. अवसरों की बेहतर पहचान और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।
- ङ. अपेक्षाकृत अल्पावधि में लोक अवस्थापना को सुचारु रूप से विकसित किया जा सके।
2. आर्थिक विकास तथा लोक अवस्थापना और सार्वजनिक सेवाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहन देकर प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू निवेश का संवर्धन करना।
 3. लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के अव्यवस्थित निष्पादन के नकारात्मक प्रभाव को सीमित करना।
 4. समस्त प्रतिभागियों के लिए समान अवसर सृजित करने तथा समस्त हितधारकों के हित संरक्षण के लिये एक पारदर्शी, सुसंगत और दक्ष प्रशासनिक तंत्र स्थापित करना।
 5. स्वामित्व वाले विभागों की सहायता से लोक निजी सहभागिता के लिए प्रस्तावित की जाने वाली परियोजनाओं की शोल्फ तैयार करना और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से अग्रसारित करना।
 6. परियोजना संरचना में जोखिम की भागीदारी करने हेतु आवश्यक ढांचा उपलब्ध कराना ताकि जोखिम ऐसे पक्ष को निर्दिष्ट किया जा सके, जो उनके प्रबंधन हेतु सर्वाधिक उपयोगी हो।
 7. लोक निजी सहभागिता के लिए सही परियोजनाओं के चयन द्वारा जनता को सतत लाभ सुनिश्चित कराने के लिए सभी परियोजनाओं में धन के सबसे अच्छे मूल्य का आकलन करने हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित करना।
 8. परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए एक प्रभावी एवं कुशल संस्थागत तंत्र स्थापित करना।
 9. लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए एक सुगठित शिकायत निवारण तंत्र/नियामक ढांचा तैयार करना।

1.6 प्राथमिकता क्षेत्र

1.6.1 इस नीति द्वारा आच्छादित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जो समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं, निम्नवत होंगे :

क्र. सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र
1.	शहरी	<ol style="list-style-type: none"> 1. शहरी परिवहन प्रणालियां/सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का सुधार, आधुनिक बस-स्टैंडों के निर्माण सहित। 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 3. सीवरेज एवं अपवहन 4. जन द्रुत परिवहन प्रणालियां 5. जल उपचार और आपूर्ति 6. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कोई भी घटक
2.	ऊर्जा	<ol style="list-style-type: none"> 1. जल विद्युत शक्ति, संचरण एवं वितरण प्रणालियां 2. अक्षय ऊर्जा उत्पादन और वितरण
3.	कृषि एवं ग्रामीण विकास	<ol style="list-style-type: none"> 1. बागबानी एवं पुष्पकृषि 2. जैविक खेती एवं स्वदेशी बीज विकास 3. कृषि उत्पादन और विपणन 4. ग्रामीण अवस्थापना 5. जल उपचार और आपूर्ति

4.	परिवहन	1. विमानपत्तन, हवाईपट्टियां और हेलीपोर्ट 2. सड़क, पुल और बाईपास, बस अड्डे, रज्जू मार्ग 3. रेलवे एवं संबंधित परियोजनाएं 4. अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और संभार केंद्र
5.	पर्यटन	1. पर्यटन और संबंधित अवस्थापना, मनोरंजन केन्द्रों सहित 2. गंतव्य विकास 3. पर्यावरणीय-पर्यटन
6.	सामाजिक	1. हेल्थकेयर अवस्थापना और माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवायें 2. शिक्षा अवस्थापना और संबंधित सेवायें
7.	व्यापार एवं उद्योग	1. औद्योगिक पार्क, थीम पार्क जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/ जैव-प्रौद्योगिकी (बीटी) पार्क, नॉलेज पार्क, विशेष आर्थिक जोन तथा टाउनशिप 2. व्यापार मेला, सम्मेलन, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक केंद्र

□ अन्य कोई भी क्षेत्र/सुविधा, जो सरकार द्वारा सम्मिलित की जाए।

1.6.2 लोक निजी सहभागिता परियोजना का परीक्षण

सभी अवस्थापना एवं परियोजनायें, जो कि पैरा (1.5.1) में उल्लिखित हैं, का लोक निजी सहभागिता परीक्षण करना अनिवार्य है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार तथा हितधारक को उसके धन का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।

2- लोक निजी सहभागिता की प्रक्रिया:-

राज्य सरकार अधिक से अधिक परियोजनाओं को पीपीपी0 मोड में बढ़ावा देना चाहती है और इसलिये नया मजबूत तन्त्र प्रस्तावित है:-

चरण-1

(अ) परियोजना पहचान के चरण:

- आवश्यकता की अभिव्यक्ति
- आवश्यकता विश्लेषण
- विकल्पों का विश्लेषण
- पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन

चरण-2

(क) परियोजनाओं की पहचान के उपरान्त की गतिविधियाँ :

- सलाहकारों/परामर्शदाताओं को किराये पर लेना
- हितधारकों से परामर्श

(ख) परियोजना की व्यवहार्यता के चरण :

- तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना
- वित्तीय व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना
- परियोजनाओं के लागत सम्बन्धी प्रस्ताव
- आर्थिक व्यवहार्यता
- विधिक संरचना का अनुपालन

(ग) परियोजना संरचना के चरण :

- I. जोखिम विश्लेषण
- II. अनुबन्धात्मक संरचना सकेतक

(घ) अधिप्राप्ति से पूर्व की गतिविधियाँ:

- I. भूमि अधिग्रहण, यदि आवश्यक हो।
- II. उपादेयता का स्थानान्तरण, यदि आवश्यक हो।
- III. परियोजना हेतु अनुमोदनों तथा अनापत्तियों का अध्ययन, जिन्हें लागू करना आवश्यक हो।
- IV. अन्तर्विभागीय समन्वय

(ङ) निविदा प्रलेखन चरण:

- I. योग्यता हेतु आवेदन
- II. प्रस्ताव के लिये आवेदन
- III. परियोजना की जानकारी के लिये ज्ञापन
- IV. अनुबन्ध पत्र आलेखन

(च) अधिप्राप्ति प्रक्रिया:

- I. व्यापक प्रतिस्पर्धी रणनीति जैसे—रोड शो
- II. एक चरण या दो चरण निविदा प्रक्रिया
- III. निजी भागीदार का चयन

(छ) अधिनिर्णय के उपरान्त अनुबन्ध प्रबन्धन की स्थिति:

- I. अनुबन्ध प्रबन्ध संरचना
- II. अनुबन्ध प्रबन्धन टीम का गठन

उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार के विभाग तथा एजेन्सियों, अधिकतम निजी बाह्य संस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये उद्योग विभाग की वेबसाइट <https://investuttarakhand.com> में पी0पी0पी0 परियोजनाओं का विवरण अपलोड करेंगी।

3. मूल सिद्धांत**3.1 मूल सिद्धांत**

यह नीति निम्नलिखित मूल सिद्धांतों द्वारा दिशा निर्देशित है :

- क. वेल्यू फॉर मनी
- ख. वर्तमान संपत्तियों का मितव्ययी उपयोग तथा अतिरिक्त संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन
- ग. सेवाओं हेतु भुगतान
- घ. न्यायसंगत अनुबंध-संरचनाएं
- ङ. अधिप्राप्ति की पारदर्शी प्रक्रिया
- च. निष्पक्ष नियामक ढांचा
- छ. समर्थ संस्थागत ढांचा
- ज. पोषणीय प्रोत्साहन और रियायतें

3.2 वेल्यू फॉर मनी का आकलन

उत्तराखण्ड सरकार सभी विभागों/एजेन्सियों को सभी परियोजनाओं के वेल्यू फॉर मनी सिद्धान्त की भावना एवं प्रक्रिया के अनुरूप आंतरिक कार्यप्रणाली को आत्मसात करने हेतु प्रोत्साहित करेगी, ताकि लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं हेतु निविदाओं के बेहतर मानदण्ड सृजित हो सकें।

प्रत्येक सेक्टर तथा परियोजना का वेल्यू फॉर मनी निर्धारण हेतु भिन्न अपेक्षाएं होंगी किंतु प्रमुख सिद्धांतों द्वारा संसाधनों का बेहतर उपयोग, जोखिम का बेहतर विभाजन और तद्वारा निर्गत सेवाओं के लिए जन साधारण को बेहतर मूल्य का सृजन सुनिश्चित किया जाएगा।

3.3 परिसंपत्तियों का पूर्ण उपयोग तथा संसाधनों का विभाजन

सरकार के पास उपलब्ध संसाधन कोष का सर्वश्रेष्ठ संभव उपयोग करने तथा नई सेवाओं से योजित लाभों हेतु प्रतीक्षाविधियों को न्यूनतम करने के क्रम में, सरकार को सर्वप्रथम वर्तमान परिसंपत्तियों का कुशल उपयोग, सुधार के उपायों और उनके माध्यम से सेवा प्रदायगी के बेहतर प्रबंधन की संभावना सृजित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

इसके फलस्वरूप लोक निजी सहभागिता प्रक्रिया द्वारा नवीनतम संपत्तियों के सृजन के लिये संसाधन आवंटन को उचित प्राथमिकता क्रम दिया जा सकेगा। इसके परिणामस्वरूप बेहतर परियोजनाएँ तैयार की जा सकेंगी, जो विद्यमान और नई परिसंपत्तियों के एकीकरण द्वारा एकीकृत अवस्थापना विकास का दृष्टिकोण सृजन करेगी।

उत्तराखण्ड सरकार सामाजिक आवश्यकता और आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहन देगी। तथापि, उत्तराखण्ड सरकार स्वीकार करती है कि सभी "सामाजिक" परियोजनाएँ लोक निजी सहभागिता के लिए पर्याप्त वाणिज्यिक प्रोत्साहन अम्यर्पित नहीं कर सकती हैं, ऐसे मामलों में सरकार अन्य प्रतिपूर्ति तंत्रों का उपयोग करेगी, जैसे कि Viability Gap Funding या वार्षिकी अथवा परिवर्धित वार्षिकी भुगतानों का प्रावधान। विकल्पतः, उत्तराखण्ड सरकार (अथवा सरकारी संस्था) ऐसी परियोजनाओं का स्वयं कार्यान्वयन कर सकती है, और जहाँ संभव हो, सेवाओं का प्रबंधन अंततः सहभागी निजी क्षेत्र (पीएसपी) को अंतरित कर सकती हैं।

उत्तराखण्ड सरकार अवस्थापना के विस्तार, प्रोन्नयन तथा/अथवा विकास के लिए निवेशों को युक्तिसंगत बनाने हेतु यथार्थ-मापदंड भी विकसित करेगी। प्रतिनिधिक रूप से, परियोजना की पहचान और प्राथमिकता क्रम निर्धारण निम्न आधारों पर नियंत्रित होगा :

क. अवस्थापना हेतु मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल का आकार;

ख. संतुलित क्षेत्रीय विकास पर फोकस, विशेष रूप से मूल अवस्थापना के प्रावधान के संबंध में;

ग. प्रत्यक्ष/अंतर-क्षेत्रीय सम्पर्कों का विकास, जहाँ महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

उत्तराखण्ड सरकार अवस्थापना परियोजनाओं में लोक निजी सहभागिता को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन देगी। अतः निवेश योग्य सार्वजनिक निधियों के एक बड़े हिस्से का उपयोग सामाजिक आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, जो निजी वित्तीय पहल के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता। दीर्घावधि अवस्थापना वित्तपोषण के लिए सरकारी निधियों का स्थायी स्रोत सृजित करने के क्रम में, उत्तराखण्ड सरकार तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों की विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आंतरिक एवं बाह्य बजटीय संसाधनों में वृद्धि की जाएगी।

3.4 सेवाओं हेतु भुगतान

3.4.1 उत्तराखण्ड सरकार स्वीकार करती है कि एक व्यवस्था में जहाँ सेवाओं का मूल्य आर्थिक रूप से पोषणीय नहीं है, उपभोक्ता संसाधनों के उपयोग में मितव्ययिता हेतु प्रोत्साहित नहीं होंगे तथा सेवाप्रदाता से अधिक दक्षता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित नहीं होंगे। उत्तराखण्ड सरकार का मानना है कि "सेवा प्रदाता-प्रभारण" तथा "उपभोक्ता-भुगतान" के सिद्धांत की मूलधारणा लोक निजी सहभागिता की सफलता का मूलमंत्र है। इस दिशा में उत्तराखण्ड सरकार, जहाँ आवश्यक और उपयुक्त है, निम्न उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता शुल्क लागू करने (टोल, शुल्क, टैरिफ, उपकर इत्यादि) पर विचार करेगी :

क. उपभोक्ता को किफायती कीमतों पर बेहतर, टिकाऊ और उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के क्रम में परियोजना संपत्तियों के निर्माण/पुनर्विकास/पुनरुद्धार/प्रतिस्थापन और उनके चालू कार्यों तथा अनुरक्षण के लिए एक स्थायी तथा समर्पित वित्तीय स्रोत का सृजन।

ख. मांग प्रबंधन

- ग. लोक निजी सहभागिता प्रोत्साहन
- घ. सेवा प्रावधान की लागत शामिल करना
- ङ. यह स्वीकार करते हुए कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग प्रयोक्ता प्रभारों में कुछ आर्थिक सहायता की अपेक्षा कर सकते हैं, परियोजना हेतु ऐसी आर्थिक सहायता सुव्यक्त करना ताकि परियोजना का आर्थिक रूप से व्यवहार्य बने रहना सुनिश्चित किया जा सके।

3.4.2 उपभोक्ता प्रभार निम्न किसी एक अथवा अधिक मानदंडों पर आधारित होगा :

- क. उपभोक्ताओं की बचत
- ख. भुगतान की इच्छा
- ग. भुगतान की क्षमता
- घ. सुव्यक्त आर्थिक सहायताओं की आवश्यकता
- ङ. विभिन्न परियोजनाओं के बीच एकरूपता
- च. वर्तमान सेवा स्तर और विचारित सुधार
- छ. लागत वसूली
- ज. ऋणसेवा और प्रतिभूति प्रतिफल

3.5 अनुबंध की संरचनाएं

3.5.1 उत्तराखंड सरकार परियोजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रभावी बनाने हेतु उपयुक्त अनुबंध की व्यवस्था करेगी। उत्तराखंड सरकार का प्रयास, निजी निवेशकों की वैध चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, अनुबंधित पक्षों के मध्य जोखिमों के न्यायसंगत विभाजन के लिए अनुबंध ढांचा तैयार करेगा। ऐसे पक्ष को जोखिम विभाजन का प्रयास किया जाएगा, जो उस जोखिम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

3.5.2 वर्तमान परिसंपत्तियां : अनुबंध/कार्यान्वयन में प्रयुक्त संरचनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

- क. निजी आपरेटर के माध्यम से परिसंपत्तियों का पूर्ण या आंशिक प्रबंधन:
 - i. पूर्व-निर्धारित अवधियों के लिए परिचालन तथा अनुरक्षण अनुबंध
 - ii. परिसंपत्तियों के लिये पट्टा/अनुज्ञप्ति
 - iii. पुनरुद्धार, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण अनुबंध

3.5.3 नई परिसंपत्तियां : परियोजना की प्रकृति के अनुसार नई परियोजनाओं हेतु प्रयुक्त अनुबंध-संरचना/अनुबंधों में अन्य के साथ निम्न शामिल होंगे :

- क. निर्माण एवं अंतरण (बी एवं टी)
- ख. निर्माण-अनुज्ञापन-अंतरण (बीएलटी)
- ग. निर्माण-अंतरण-प्रचालन (बीटीओ)
- घ. निर्माण-प्रचालन-अंतरण (बीओटी)
- ङ. निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन-अंतरण (बीओओटी)
- च. निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन (बीओओ)
- छ. निर्माण-प्रचालन-अंश-अंतरण (बीओएसटी)
- ज. निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन-अंश-अंतरण (बीओओएसटी)

- झ. निर्माण-स्वामित्व-अनुज्ञापन-अंतरण (बीओएलटी)
- ञ. डिजाइन-निर्माण-वित्तपोषण-प्रचालन-अंतरण (डीबीएफओटी)
- ट. पुनरुद्धार-वित्तपोषण-प्रचालन-अंतरण (आरएफओटी)

3.5.4. विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी0)

जहां कहीं उपयुक्त है, उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड सरकार की एजेंसियां अवस्थापना परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन हेतु किसी एसपीवी की इक्विटी संरचना में भाग ले सकती है। एसपीवी में भाग लेने हेतु पीएसपी के चयन में उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। एसपीवी की इक्विटी संरचना का निर्णय प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर अलग-अलग किया जाएगा।

3.6. अधिप्राप्ति प्रक्रिया

3.6.1. मूलतः सभी पीपीपी अनुबंध उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अधीन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्द्धी निविदा प्रक्रिया के आधार पर किए जाएंगे।

सभी मामलों में अधिनिर्णय संबंधी मानदंड सुस्पष्ट व्यक्त किए जाएंगे। अधिप्राप्ति प्रक्रिया परियोजना के आधार पर अथवा जटिलता के स्तर पर और प्रतिस्पर्द्धी निविदा को प्रोत्साहित करने के लिए, एकल-चरण अथवा दो-चरणों में पूर्ण की जा सकती है।

एकल निविदा तथा अव्यवहार्य/काल्पनिक निविदाओं के संचालन हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

3.6.2. इस प्रयोजन के लिये उत्तराखंड सरकार आवश्यक तकनीकी योग्यताधारक, भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नामित सलाहकारों की सेवाओं का उपयोग कर सकती है। साधारणतः, अधिप्राप्ति प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होंगे :

- क. परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी
- ख. अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई/योग्यताओं हेतु अनुरोध (आरएफक्यू)
- ग. आरएफपी तथा डीसीए के अनुमोदन
- घ. प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आरएफपी)
- (i) तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव
- च. निविदाओं का तकनीकी तथा वित्तीय मूल्यांकन
- छ. लोक निजी सहभागिता भागीदार(रों) का चयन
- ज. अनुबंध पर हस्ताक्षर

3.6.3. प्रारंभिक चयन मानदंड निम्नलिखित पूर्व-योग्यता प्राचलकों पर आधारित होंगे:

- क. निविदादाता की वित्तीय क्षमता-शुद्ध मूल्य, विगत तीन वर्षों में औसत टर्नओवर, संपत्ति आधार इत्यादि।
- ख. पूर्णकालिक कुशल कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या
- ग. सम्बद्ध गुणवत्ता प्रमाणन (आईएसओ 9000, आईएसओ 14000 इत्यादि)

- घ. उस सेक्टर में परियोजनाओं की न्यूनतम संख्या (सुनिश्चित मूल्य की) का उत्तरदायित्व निर्वहन किया होना चाहिए।
- इ. उस सेक्टर में परियोजनाओं के सफल समापन का ट्रैक रिकॉर्ड

3.6.4. चयन हेतु प्रयुक्त मानदंडों में उद्देश्यात्मक तकनीकी/वित्तीय प्राचलक सम्मिलित होंगे, जैसे कि :

- क. सेवा का स्तर, प्रस्तावित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता;
- ख. व्यवहार्यता अनुदान सहायता का न्यूनतम वर्तमान मूल्य;
- ग. भूमि का न्यूनतम परिमाण;
- घ. सरकार से परिसंपत्ति आधारित सहायता का न्यूनतम वर्तमान मूल्य
- इ. राजस्व का अधिकतम अंश (अथवा वर्तमान मूल्य)
- च. न्यूनतम यूनिट मूल्य अथवा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भुगतानों का वर्तमान मूल्य;
- छ. अधिकतम प्रत्यक्ष भुगतान (अथवा प्रत्यक्ष भुगतानों का वर्तमान मूल्य);
- ज. भावी भुगतानों का अधिकतम वर्तमान मूल्य
- झ. न्यूनतम रियायत अवधि;
- ञ. न्यूनतम यूनिट मूल्य अथवा उपभोक्ता शुल्कों का वर्तमान मूल्य;
- ट. प्रस्तावित इक्विटी शेयरों का अधिकतम प्रीमियम (अथवा वर्तमान मूल्य);
- ठ. प्रस्तावित धन हेतु सर्वश्रेष्ठ मूल्य।
- ड. न्यूनतम वार्षिकी
- त. न्यूनतम संशोधित वार्षिकी

3.7 नियामक संरचना

उत्तराखण्ड सरकार की अवधारणा है कि लोक निजी सहभागिता मॉडल के अधीन अवस्थापना के सृजन में यह अपेक्षित है कि उसमें ऐसी प्रतिस्पर्धी सुविधाओं का सृजन नहीं होने का पर्याप्त आश्वासन होना चाहिए, जो परियोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता को यथार्थतः प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ऐसी एकाधिपत्यवादी स्थितियों का स्वतंत्र नियंत्रण सुनिश्चित करना भी सरकार का दायित्व होगा ताकि प्रयोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं दोनों के हित दृष्टिगत रखना सुनिश्चित किया जा सके।

उत्तराखण्ड सरकार का आशय कुछ अवस्थापना सेक्टरों के लिए पृथक नियामक प्राधिकरण स्थापित करना है। नियामक की भूमिका में प्रवेश तथा निकास के लिए प्रतिमान निर्धारण, शुल्क दर नियतन, सुविधाओं/सेवाओं के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के लिए मानदंड निर्धारित करना, निजी भागीदारी और सरकारी एजेंसी के बीच राजस्व भागीदारी तय करना, परियोजना अवधि के दौरान निजी भागीदारी के एकपक्षीय निकास से बचने के लिए बैंक गारंटियों, संपादित अथवा किसी ऐसे दस्तावेज के रूप में निकास अवरोधों का दृढ़ीकरण सम्मिलित होगा।

तथापि, नियामक प्राधिकरणों के गठन का निर्णय प्रत्येक सेक्टर की विशिष्टताओं के आधार पर किया जाएगा और वृहत् स्तर पर लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के गठन से पूर्व नियामक संरचना का गठन करना उचित होगा।

3.8 संस्थागत व्यवस्था

उत्तराखण्ड सरकार एक प्रभावी एवं दक्ष संस्थागत तंत्र की आवश्यकता को मान्यता देती है और इसलिए नीति के उद्देश्यों की ओर बढ़ने के लिए आवश्यकता समितियाँ तथा सशक्त समूहों का गठन करती है।

3.8.1 व्यय वित्त समिति (EFC)

उत्तराखण्ड सरकार पीपीपी के तहत राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा के लिए मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सचिवों के एक समूह से मिलकर व्यय वित्त समिति (ईएफसी) का गठन करेगी। राज्य नोडल अधिकारी पीपीपी, प्रमुख सचिव, नियोजन/सचिव, नियोजन, ईएफसी के सदस्य सचिव होंगे। पैरा 4.1.3 और 4.1.5 में वर्णित सभी पीपीपी परियोजनाओं को ईएफसी की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

3.8.2 ईएफसी की भूमिका

ईएफसी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के विकास, विभिन्न स्रोतों से निजी भागीदारी और वित्त पोषण से संबंधित राज्य सरकार के सभी प्रयासों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी होगी।

3.8.3 ईएफसी की शक्तियाँ और कार्य

ईएफसी की शक्तियाँ और कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- (क) पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता देना, अनुमोदन करना और व्यय स्वीकृत एवं प्राधिकृत करना।
- (ख) पैरा 4.1.4 और 4.1.5 में उल्लिखित अनुमोदित परियोजनाओं की राज्य मंत्रिमण्डल को संस्तुति करना।
- (ग) इस नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य विभागों के प्रयासों का समन्वय करना।
- (घ) किसी भी पीपीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन, निष्पादन, संचालन और प्रबंधन का निरीक्षण, दौरा, समीक्षा और निगरानी करना।
- (ङ) परियोजना के लिए वांछनीय उपयुक्त नियामक तंत्र, सुगठित शिकायत तिवारण तंत्र के गठन हेतु विशेष विधान का अधिनियमन संस्तुत करना।
- (च) पीपीपी पहलों को शुरू करने वाले लाइन विभागों को फ्रेमवर्क और दिशानिर्देश जारी करना।
- (छ) पीपीपी परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- (ज) EFC नीति, विनियामक और किसी भी प्रासंगिक परिवर्तन के लिए संचालक होगी।
- (झ) विभागों, निजी क्षेत्र, नागरिकों आदि के बीच पीपीपी पहलों के बारे में जागरूकता का अनुमोदन।
- (ट) परियोजना प्रारंभकर्ता विभाग के साथ परामर्श से निजी भागीदार के लिए विशिष्ट सेवा स्तरों का अनुमोदन करना तथा निजी भागीदार और परियोजना पहलकर्ता विभाग के बीच सेवा स्तर अनुबन्ध (एसएलए) का सूत्रबद्ध किया जाना सुनिश्चित करना।
- (ठ) लोक निजी सहभागिता के अधीन प्रारंभ किए गए परियोजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना तथा वित्तीय एवं भौतिक दोनों प्रकार के लक्ष्यों के सम्बन्ध में उपलब्धियों का विश्लेषण करना और सुधार उपायों, यदि अपेक्षित हैं का निर्णय करना।
- (ड) पीपीपी परियोजनाओं के सफल निष्पादन के लिए विभिन्न स्तरों पर उचित क्षमता निर्माण की पहल सुनिश्चित करना।
- (ढ) राज्य में पीपीपी पहल के लिए उचित संचार रणनीतियों का विकास और विकास सुनिश्चित करना।
- (ण) सुनिश्चित करना कि पारदर्शिता और उत्तरदायिता के उच्चतम मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त लेखा-परीक्षा तथा अनुश्रवण मानक विकसित और अनुरक्षित किए गए हैं।
- (त) समय-समय पर, इसके विभिन्न विशेषज्ञों/सदस्यों तथा/अथवा समिति के स्टाफ (लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ) के मध्य से कोई समितियाँ/उप-समितियाँ गठित करना और उनको विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपना।
- (थ) निजी भागीदारी को अनुबन्ध अवार्ड होने के उपरान्त, व्यय-वित्त समिति PPP सेल के माध्यम से प्रोजेक्ट की प्रगति का अनुश्रवण भी करेगी एवं यह सुनिश्चित करेगी कि निजी पार्टनर ने सिंगल विंडो क्लियरेंस रूट के माध्यम से सभी क्लियरेंस समय पर प्राप्त कर लिए हैं।

3.8.4 लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ एवं तकनीकी सचिवालय

इस नीति के अन्तर्गत सुनिश्चित कार्यों के संचालन में ईएफसी की सहायता नियोजन विभाग एवं उसमें स्थापित पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा की जायेगी।

तकनीकी सचिवालय और राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य आधारभूत परियोजना विकास संस्थाओं द्वारा पीपीपी सेल को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

पीपीपी परियोजना से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग आवश्यकतानुसार परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता है। परामर्शदाताओं की नियुक्ति संगत नियमों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सेन्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस द्वारा की जाएगी। नियोजन विभाग एवं उसके अधीन स्थापित पीपीपी प्रकोष्ठ पीपीपी परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त करने उन्हें ईएफसी एवं कैबिनेट के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु नोडल एजेंसी होगा।

लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ सभी निवेश प्रस्तावों की संवीक्षा तथा मंजूरी प्रदान करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित, निजी निवेश के संभाव्यता अध्ययन हेतु दिशानिर्देश तैयार करने में सहायता, उपयुक्त मानक अधिप्राप्ति प्रलेख और अनुबन्ध प्रारूप तैयार करना और विकासकों की अधिप्राप्ति में सरकार/सरकारी एजेंसियों की सहायता करेगा।

लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ, अवस्थापना परियोजनाएं लोक निजी सहभागिता प्रारूप में त्वरित गति से विकसित तथा कार्यान्वित करने में भी सरकार/सरकारी एजेंसियों की सहायता करेगा।

लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ राज्य में कार्यरत समस्त बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अभिसूत्रण, कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग में भी उत्तराखण्ड सरकार की सहायता करेगा।

लोक निजी सहभागिता सेल के माध्यम से पीपीपी पॉलिसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रारम्भिक वित्त पोषण बजटीय सहायता के माध्यम से किया जायेगा।

3.8.5 लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ के कार्य

लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ के कार्यों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे :

- क. स्वामित्व वाले विभाग/एजेंसी के साथ परामर्श से परियोजनाओं को चिन्हित कर, परिकल्पना और एक शेल्फ तैयार करने में सहायता करना।
- ख. भिन्न सेक्टरों में महत्वपूर्ण परियोजनाएं चिन्हित करने में सहायता करना जिन पर शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- ग. ऐसी परियोजनाएं चिन्हित करने में सहायता करना जहां नेटवर्क विस्तार के महत्वपूर्ण लाभों का दोहन एकीकृत अवस्थापना विकास के लिए किया जा सकता है।
- घ. राज्य सरकार द्वारा बहुपक्षीय/द्विपक्षीय निधीयन तथा/अथवा निजी क्षेत्र की सहभागिता द्वारा परियोजना कार्यान्वयन हेतु निधीयन का निर्णय करने हेतु धन का मूल्य सिद्धांत के अधीन परियोजनाओं के मूल्यांकन और आकलन के लिए संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ परामर्श सहायता से आंतरिक मूल्यांकन दिशानिर्देश विकसित करना।

- इ. ऐसी परियोजनाओं का लोक निजी सहभागिता हेतु अनुमोदन के लिए ई0एफ0सी0 को संस्तुत करना।
- च. भिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों को पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में स्वयं अथवा परामर्शदाताओं के माध्यम से सहायता करना।
- छ. परियोजनाएं विकासकर्ता चयन के चरण तक पहुंचाने के लिए, संबंधित विभाग/एजेंसी के साथ परामर्श से परामर्शदाता की नियुक्ति/चयन करना।
- ज. नियोजन विभाग के माध्यम से वीजीएफ तथा ऐसे प्रयोजन हेतु सृजित किसी अन्य निधि को जुटाने हेतु नीति आयोग, भारत सरकार (जीओआई) तथा अन्य निधीयन एजेंसियों जैसे कि विश्व बैंक के साथ अन्योन्य क्रिया करना।
- झ. नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय/द्विपक्षीय निधीयन की आवश्यकता संस्तुत करना।
- ञ. राज्य में लोक निजी सहभागिता हेतु क्षमता निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करना। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यह सरकार के विभिन्न स्तरों पर लोक निजी सहभागिता के विषय में आवश्यक दौरे और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन/अनुशंसा करेगा।
- ट. परियोजना की अपेक्षानुसार उपयुक्त नियामक तंत्र/सुगठित शिकायत निवारण तंत्र की अनुशंसा करना।
- ठ. यूआईडीएफ से, परियोजनाओं के विकास, निधीयन के अंतराल के लिए लोक निजी सहभागिता की अपेक्षाओं तथा इस नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी अन्य अपेक्षा की अनुशंसा करना।
- ड. निधि के सृजन, व्यवस्था और मानीटरिंग हेतु किसी विधान, यदि अपेक्षित है, का अभिसूत्रण और अनुशंसा करना।
- ढ. राज्य में लोक निजी सहभागिता हेतु ज्ञान कोष के रूप में कार्य करना।
- ण. उत्तराखण्ड सरकार, अवस्थापना परियोजना विकास और कार्यान्वयन की सुगमता जनमत और स्टैकहोल्डरों की सहभागिता की भूमिका भी स्वीकार करती है। चूंकि परियोजना की व्यवहार्यता अंतिम प्रयोक्ता की लागत पर निर्भर है, अतः "बाजार क्या वहन कर सकता है" का सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जनमत जुटाना और हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करना अवस्थापना परियोजना का अभिन्न अंग है। लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ इस प्रक्रिया की सुगमता व्यवसायिक निकायों, एनजीओ उद्योग संघों तथा उपभोक्ता समूहों का सहयोग प्राप्त करेगा।
- त. संस्थागत ढांचे में ऐसे अवरोधों जिनके द्वारा निवेश अवरुद्ध किए जाने की संभावना है को चिन्हित करना तथा उन्हें दूर करने और लोक निजी सहभागिता के माध्यम से अवस्थापना विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना।
- थ. अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन चरण में परिवर्तन सुसाध्य बनाना।
- द. राज्य में समस्त लोक निजी सहभागिता तथा ईएपी परियोजनाओं हेतु और कार्यान्वयन मानीटरिंग हेतु एक सुगठित मानीटरिंग ढांचा तैयार करना।
- ध. लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ, प्रत्येक सेक्टर के लिए तैयार की गई कार्यनीति के आधार पर, उत्तराखण्ड सरकार के विभागों/एजेंसियों के साथ परामर्श कर राज्य में अवस्थापना विकास हेतु एक मार्ग मानचित्र (रोड मैप) तैयार करेगा।

3.8.6 रेखीय विभागों में लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ का सृजन

राज्य लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ के साथ समन्वय हेतु तथा लोक निजी सहभागिता की पहल को आगे बढ़ाने के लिए समस्त रेखीय विभागों/एजेंसियों में लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे।

3.8.7 लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ/जिला स्तर समिति का सृजन

उत्तराखण्ड सरकार जिला स्तर पर एक जिला लोक निजी सहभागिता समिति गठित करेगी, जो लोक निजी सहभागिता के माध्यम से मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने की सुगमता सहित अवस्थापना परियोजनाओं के समन्वय और कार्यान्वयन में सहायता करेगी।

जिला लोक निजी सहभागिता समिति की अध्यक्षता संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी। यदि आवश्यक है तो, जिला समिति उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नामित उपयुक्त पदस्तर के अधिकारियों और राज्य स्तरीय औद्योगिक फोरम द्वारा नामित निजी क्षेत्र के अधिकतम 3 प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी।

4. परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया

4.1 परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया

लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के उपक्रमी प्रशासनिक विभाग को प्रत्याशित/अल्पसूचीकृत निविदाकर्ता से कोई वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित करने से पूर्व निम्नलिखित परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगा:

4.1.1 लोक निजी सहभागिता प्रणाली के अन्तर्गत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रक्रिया:

इस नीति की धारा-2 में वर्णित चरण-1 की गतिविधियों को पूरा करने के बाद प्रशासनिक विभाग पीपीपी सेल को अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों और चर्चा के लिए प्रस्ताव भेजेगा। जिसके उपरान्त एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (PPR) का मसौदा तैयार किया जाएगा। PPR में विभिन्न व्यय/अध्ययन/परामर्श आदि के बारे में सांकेतिक प्रावधान होंगे, जो कि स्टेज-2 प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होंगे।

तदुपरान्त प्रशासनिक विभाग सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेगा। इसके अलावा, स्टेज-2 गतिविधियों के लिये प्रशासनिक विभाग अपने सलाहकार सहित स्टेट पीपीपी सेल से समन्वय कर परियोजना सम्बन्धी कार्य करेगा।

जिन प्रशासनिक विभागों के पास उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अनुलग्नक I-IV के अनुसार पर्याप्त सूचनाएँ उपलब्ध हों, को इस नीति के चरण-1 की प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे चरण-2 की प्रक्रिया का पालन करेंगे।

प्रशासनिक विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त नियम एवं शर्तों के अनुरूप समस्त प्रस्ताव सन्दर्भित किये जायेंगे।

4.1.2 पांच करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत वाली पीपीपी परियोजनाओं के लिए नियम:

(अ) 5.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत वाली पीपीपी परियोजनाओं को प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त की अध्यक्षता वाली "वित्त पीपीपी समिति" द्वारा अनुमोदित किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे:-

- प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन अथवा प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन द्वारा नामित अपर सचिव स्तर से अन्यून पद के अधिकारी।
- अपर सचिव, वित्त विभाग (सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग)।
- पीपीपी विशेषज्ञ।

- प्रशासकीय विभाग का सचिव
 - सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
- (ब) प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा उपर्युक्त समिति के सम्मुख परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।
- (स) उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने पर परियोजना प्रस्ताव पर वित्त विभाग का अन्तिम अनुमोदन माना जायेगा। इसके उपरान्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की पृथक से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

4.1.3 प्रशासनिक विभाग द्वारा पाँच करोड़ रुपये से अधिक या 50 करोड़ ₹0 से कम की परियोजना लागत वाली पीपीपी परियोजनाओं के लिए निम्नानुसार गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा:-

(अ) 5.00 करोड़ या उससे अधिक अथवा 50 करोड़ से कम लागत की पीपीपी परियोजनाओं के लिये मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा, जिसमें निम्न सदस्य होंगे:-

- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त
- प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन
- प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग
- प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन
- प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य
- प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय
- प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव (विशेष आमन्त्री)

4.1.4 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत की पीपीपी परियोजनाओं के लिए, प्रशासनिक विभाग निम्नलिखित प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करेगा:

- (क) व्यय वित्त समिति (EFC) से वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार।
- (ख) EFC की संस्तुति के आधार पर प्रशासनिक विभाग परियोजना प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से कैबिनेट के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ग) राज्य मंत्रिमंडल द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

4.1.5 परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया का सारांश

क. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विकसित लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए

लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं की परियोजना लागत (करोड़ ₹0)	सैद्धांतिक अनुमोदन	वित्त पीपीपी समिति से अनुमोदन	ईएफसी	राज्य मंत्रिमंडल
5 करोड़ रुपए तक	हां	हां	नहीं	नहीं
5 करोड़ रुपए अथवा अधिक किंतु 50 करोड़ रुपए से कम	हां	नहीं	हां	नहीं
50 करोड़ रुपए अथवा अधिक	हां	नहीं	हां	हां

4.1.6 परियोजना लागत की परिभाषा:

इस उद्देश्य के लिये 3.1.6A में उल्लिखित परियोजना लागत में शामिल होंगे:-

(क) राजस्व प्रदान करने वाली वाणिज्यिक परियोजनाओं हेतु-

परियोजना लागत में सिविल निर्माण हेतु अनुमानित पूंजी निवेश, उपकरण, फर्नीचर, फिक्सर, वाहन या किसी अन्य उपकरण की खरीद, परियोजना हेतु भौतिक सम्पत्ति की आवश्यकता या परियोजना विकास खर्च, वित्त पोषण और अन्य आकस्मिक शुल्क शामिल होंगे, अथवा

(ख) संचालन एवं रखरखाव परियोजना हेतु-

परियोजना के प्रथम वर्ष में परियोजना संचालन एवं रखरखाव हेतु निजी भागीदार को परियोजना से अर्जित होने वाली अनुमानित राजस्व प्राप्ति की धनराशि परियोजना लागत होगी।

(ग) गैर राजस्व प्रदान करने वाली परियोजनाओं, दक्षता विकास/लागत बचतकारी परियोजना (प्रबन्धन या सेवा अनुबन्ध या अभियान्त्रिकी, प्रदर्शन आधारित संचालन तथा रखरखाव अनुबन्ध और वार्षिकी अथवा संशोधित वर्षवार आधारित अनुबन्ध)-

परियोजना लागत में निम्न लागत/धनराशि शामिल होगी:-

(i) निजी भागीदार द्वारा अनुमानित पूंजीगत निवेश के अन्तर्गत सिविल निर्माण, उपकरणों, फर्नीचर, उपकरण, फर्नीचर, फिक्सर, वाहन या किसी अन्य उपकरण की खरीद, परियोजना हेतु भौतिक सम्पत्ति की आवश्यकता या परियोजना विकास खर्च, वित्त पोषण और अन्य आकस्मिक शुल्क शामिल होंगे, और/अथवा

(ii) सरकार द्वारा रियायत अवधि में निजी भागीदार को अनुमानित वर्तमान राजस्व/पूंजीगत लागत को वार्षिक आधार पर अनुदान के रूप में देय किया जायेगा।

4.2 शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं इत्यादि

क. स्थानीय शहरी निकाय प्रस्तावों पर अपने सम्बन्धित बोर्डों से अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा प्रशासकीय विभाग यथा शहरी विकास के माध्यम से अग्रेत्तर अनुमोदन की कार्यवाही के लिए प्रस्ताव अग्रसारित करेगा, जैसा कि इस नीति के पैरा-4.1 में उल्लिखित किया गया है।

ख. स्थानीय ग्रामीण निकाय प्रस्तावों पर अपने सम्बन्धित बोर्डों से अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा प्रशासकीय विभाग यथा पंचायतीराज के माध्यम से अग्रेत्तर अनुमोदन की कार्यवाही के लिए प्रस्ताव अग्रसारित करेगा, जैसा कि इस नीति के पैरा-4.1 में उल्लिखित किया गया है।

4.3 सरकारी स्वाधिकृत कम्पनियां, संस्थाएं, संयुक्त उद्यम इत्यादि

क. इन स्वतंत्र सरकारी संस्थाओं को इस नीति में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

4.4 लोक निजी सहभागिता व्यवस्था के अंतर्गत विकसित परियोजनाओं हेतु अनुमोदन प्रक्रिया

चूंकि लोक निजी सहभागिता परियोजना विकास प्रक्रिया एक तकनीकी विषय है तथा इसमें परियोजना संरचना हेतु जटिल मूल्यांकन प्रक्रियाएं अर्न्तनिहित हैं, अतः संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव लोक निजी

सहभागिता परियोजना विकास प्रक्रिया, संवीक्षा और मूल्यांकन का उत्तरदायित्व संभालने के लिए विभागाध्यक्ष और सचिवालय दोनों स्तरों पर आवश्यक तकनीकी और परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञताधारक अधिकारियों को चिन्हित कर सकते हैं।

4.5 डेवलपर्स का अनुमोदन

निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात प्रशासनिक विभाग द्वारा चयनित अनुदानग्राही के विषय में अंतिम अनुमोदन संबंधित विभागीय मंत्री से प्राप्त किया जाएगा।

4.6 विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) के माध्यम से विकास

एसपीवी का गठन, जैसे और जब इस नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और साकार करना अपेक्षित होगा, किया जाएगा और परियोजना को गति प्रदान करने हेतु विशेष प्रयोजन साधनों में विभिन्न मंजूरी तथा अनुमतियां प्राप्त की जाएंगी।

5. अनुश्रवण, मूल्यांकन और निर्धारण तंत्र

लोक निजी सहभागिता कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये एक सुगठित मानीटरिंग, मूल्यांकन और आकलन ढांचा विकसित तथा उपयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा।

5.1 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ढांचे में रेखीय विभागों से संबंधित प्रत्येक लोक निजी सहभागिता परियोजना के अधीन परियोजना डिजाइन और समय पर कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। नियोजन विभाग के अधीन स्थापित लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ राज्य में समस्त परियोजनाओं के समग्र मानीटरिंग और मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी होगा।

लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं का नियमित पुनरीक्षण और अनुश्रवण किया जाएगा। लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के निष्पादन में लगे सभी विभाग/एजेंसियां नवीनतम विकास के संबंध में लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ को सूचना/डेटा उपलब्ध कराएंगे।

इस संबंध में लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अधीन निभाई जाने वाली मुख्य भूमिकाओं का उल्लेख नीचे किया गया है :-

5.1.1 परियोजना अनुश्रवण

परियोजना अनुश्रवण के अधीन, लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ और तकनीकी सचिवालय द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिकाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

क. मानक प्रलेखों, प्रपत्रों तथा परियोजना प्लान सांचों के रूप में कार्यक्रम अनुश्रवण साधनों का चिन्हिकरण एवं डिजाइन करना।

ख. विभागों और अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में परियोजना टीमों के लिए क्षमता निर्माण दिशानिर्देशों का सहायता विकास।

ग. व्यक्तिगत परियोजनाओं, पथ विचलनों का वित्तीय और भौतिक अनुश्रवण और समाधान हेतु प्रमुख कार्यवाही क्षेत्रों की पहचान सुनिश्चित करना।

घ. मुख्य परियोजना मापों पर प्रगति रिपोर्ट हेतु प्रक्रिया स्थापना एवं व्यवस्था। इस हेतु लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ को अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ढांचा तैयार करने हेतु एक एजेंसी नामांकित करने की आवश्यकता हो सकती है।

ङ. राज्य की लोक निजी सहभागिता पहल के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की समीक्षा/समाप्ति के लिए प्रलेख सुलभ बनाने हेतु प्रक्रिया स्थापना।

5.1.2 परियोजना मूल्यांकन तथा प्रभाव आकलन

परियोजना मूल्यांकन तथा प्रभाव आकलन के अधीन, लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ द्वारा निर्माई जाने वाली प्रमुख भूमिकाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

- क. विभागों और परियोजना मूल्यांकन तथा प्रभाव आकलन के क्षेत्र में परियोजना टीमों के लिए क्षमता निर्माण दिशानिर्देशों का सहायता विकास।
- ख. सुनिश्चित करना कि सभी परियोजनाओं हेतु व्यक्तिगत परियोजना मूल्यांकन और प्रभाव आकलन किया गया है।
- ग. सहभागी विभागों के लिए, प्रसंग विषयों यथा सेवा स्तर अनुबंध प्रारूपण इत्यादि के रूप में एक परियोजना संदर्भ दिशानिर्देश तैयार एवं प्रसारित करना।
- घ. परियोजना मूल्यांकन और प्रभाव आकलन के सरलीकरण के लिये प्रक्रिया निर्धारण, जिसमें परियोजना मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन के निष्पादन हेतु परामर्शदाताओं/संगठनों का नामांकन और डेटा संग्रहण, आधार-रेखांकन और निष्पादन आकलन के लिये तृतीय पक्ष की नियुक्ति सम्मिलित होगी।

6. जोखिम निर्धारण तंत्र

अवांछित घटनाओं में जोखिम की संभावना रहती है, जो परियोजनाओं के उद्देश्यों तथा परिणामों की उपलब्धि को क्षति पहुंचा सकती हैं। एक सुगठित जोखिम आकलन ढांचा स्थापित किया जाएगा जो राज्य लोक निजी सहभागिता पहलों की सहायता जोखिम के पर्याप्त और सामयिक आकलन में करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि जोखिम कम करने के उपयुक्त उपाय किए गए हैं। उत्तराखण्ड सरकार समय-समय पर प्रजातीय (जेनेरिक) जोखिमों पर मार्गदर्शन टिप्पणियां जारी करेगी।

7. राज्य द्वारा सहयोग

राज्य सरकार, जहां कहीं अपेक्षित होगा विशिष्ट प्रोत्साहन करने हेतु और शुल्क दर निर्धारण, मूल्य निर्धारण, मध्यस्थता, सुरक्षा एवं प्रचालनात्मक मानकों इत्यादि के लिए तंत्र स्थापित करने हेतु सेक्टर विशिष्ट नीतियां तैयार करेगी। यह अवस्थापना सेक्टरों के मध्य समन्वय और सेक्टर-योजनाओं में सामंजस्य पर भी विचार कर रही है।

राज्य सहायता में निम्न सम्मिलित होंगे :

7.1 प्रशासनिक सहायता

राज्य सरकार राज्य में विकसित सभी अवस्थापना परियोजनाओं को आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रस्तुत करेगी, जिसमें सम्मिलित होंगे :-

- क. परियोजना हेतु अपेक्षित समस्त राज्य एवं केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करना।
- ख. समस्त पुनरुद्धार एवं पुनर्वास गतिविधियां, यदि ऐसा अपेक्षित है, राज्य सरकार की पुनरुद्धार एवं पुनर्वास नीति के अनुसार सुसाध्य बनाना तथा उपयोगिताओं के स्थानांतरण की जहाँ आवश्यकता हो, नीति तैयार करना।
- ग. कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की व्यवहार्यता संवर्धन हेतु विभिन्न केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं (जैसा कि लागू हो) के अधीन लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण।
- घ. परियोजना स्थल पर बिजली और पानी की आपूर्ति का प्रावधान सुगम बनाना।

इ. परियोजना हेतु आवश्यक भूमि के अधिग्रहण को सुगम बनाना।

7.2 वित्तीय सहायता

परियोजनाओं हेतु निविदा उत्तराखण्ड सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की एजेंसी से आवश्यक वित्तीय सहायता के आधार पर लगाई जा सकती है। ऐसी वित्तीय सहायता वार्षिक एक-मुश्त भुगतानों, निष्पादन से जुड़े भुगतानों के रूप में हो सकती है तथा इसका निधीयन उत्तराखण्ड सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की एजेंसी द्वारा किए गए बजटीय आवंटनों से किया जाएगा।

भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध व्यवहार्यता अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार भी आकस्मिक अवस्थापना परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने और कार्यान्वयन में सहायता के लिए, खुली निविदा से प्राप्त हुए व्यवहार्यता अंतराल के शेष भाग नकद में अथवा अन्य रियायतों द्वारा अंशदान उपलब्ध करा सकती है।

8. हितधारकों के अधिकारों का संरक्षण

उपभोक्ता, विकासकर्ताओं, स्थानीय समुदाय और ऋणदाताओं, जिनको सामूहिक रूप से हितधारक कहा जाता है, के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। विभिन्न विचारित तंत्रों में निम्न सम्मिलित होंगे :-

- क. स्थानीय समुदायों की हितों की रक्षा करते हुए, परियोजना के सफल और समयबद्ध कार्यान्वयन प्रचालन के लिये पर्याप्त विधायी एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान कराना।
- ख. उपभोक्ता प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के लिये पर्याप्त विधायी एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना।
- ग. समस्त हितधारकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु MCA's का अंगीकरण, अनुकूलन तथा विकास और समस्त परियोजना प्रलेखों में आवश्यक उपबंध समाविष्ट करना।
- घ. सेवा मानदंडों, राजस्व धाराओं तथा न्यायसंगत उपभोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण और जहां कहीं लागू हो, उपभोक्ताओं के छूट की व्यवस्था समाविष्ट करते हुए, रियायत अनुबंधों की संरचना करना।
- इ. स्वतंत्र नियंत्रक अपीलीय फोरमों तथा अन्य सुगठित विवाद निस्तारण तंत्र की स्थापना करना।
- च. परियोजना अनुमोदन के लिये हितधारक की अपेक्षा के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर हितधारक से परामर्श प्राप्त करना।
- छ. सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन समय पर सूचना उपलब्ध कराना।

9. नीति की अवधि और समीक्षा

यह नीति इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से लागू होगी तथा भविष्य में नई लोक निजी सहभागिता नीति प्रख्यापित होने तक लागू रहेगी।

इस नीति की समीक्षा, हितधारकों से प्राप्त सुझावों इत्यादि के समालोचनात्मक आकलन के आधार पर की जाएगी तथा आवश्यक एवं वांछनीय विचारित परिवर्तन समाविष्ट किए जाएंगे।

सरकार की अवधारणा है कि अवस्थापना के प्राक्धान में लोक निजी सहभागिता के दायरे में विस्तार और संस्थागत कारणों से वर्तमान विधायी संरचना में उपयुक्त परिवर्तनों की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। लोक निजी सहभागिता हेतु विशिष्ट विधायी अवरोधों पर भी, समीक्षा के दौरान विचार किया जाएगा एवं ध्यान दिया जाएगा।

नोट : इस नीति में प्रवृत्त किसी अधिनियम/नियम/उपनियम/विनियम आदि के प्रावधानों के मध्य विरोधाभास होने की स्थिति में संबंधित अधिनियम/नियम/उपनियम/विनियम आदि के प्रावधान प्रभावी होंगे, परन्तु ऐसे प्रावधानों को इस नीति के अनुरूप पीपीपी प्रस्ताव विकसित एवं क्रियान्वित करने में बाधक होने की स्थिति में प्रस्तावक प्रशासकीय विभाग को यथा-आवश्यकता संबंधित अधिनियम/नियम/उपनियम/विनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से छूट प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

आदेश : आदेशित किया गया कि प्रस्ताव उत्तराखंड गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा उसकी प्रतियां समस्त सरकारी विभागों, समस्त विभागाध्यक्षों तथा महालेखाकार, उत्तराखंड को अग्रेषित की जाएं।

राज्यपाल के आदेश द्वारा

मेजर योगेन्द्र यादव,
अपर सचिव।

UTTARAKHAND PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) REVISED POLICY-2019

August 04, 2020

No. 95/XXVI/दो(15)/2011

Table of Contents

1. INTRODUCTION & POLICY OBJECTIVE--
2. PPP PROCESS--
3. CORE PRINCIPLES--
4. PROJECT APPROVAL PROCESS--
5. MONITORING, EVALUATION AND ASSESSMENT FRAMEWORK--
6. RISK ASSESSMENT FRAMEWORK--
7. STATE SUPPORT--
8. PROTECTION OF STAKEHOLDER RIGHTS--
9. DURATION AND REVIEW OF POLICY--

No. 95/XXVI/दो(15)/2011

1. INTRODUCTION & POLICY OBJECTIVE

1.1. Introduction

- 1.1.1. Uttarakhand state came into existence on November 9, 2000 with primary objective of bringing development to hill region of the state.

In the era of globalization, it is imperative for the governments to improve the public infrastructure in order not only to build competitive advantage but also to ensure inclusive and sustainable development of nation/state as a whole, by increasing outreach of investments to all parts of the nation.

Government of India aim at achieving US \$ 5 Trillion economy by 2024-25. It has been envisaged that a large part of this investment would have to come from the private sector. Therefore, private sector needs to be actively engaged and encouraged to participate in infrastructure development and improvement of service delivery in existing infrastructure as well.

- 1.1.2. Public Private Partnership (PPP) is one of the best tools to engage the private sector in investment into public infrastructure development to :

- a. complement government's efforts,
- b. supplement resources available to government,
- c. bring in operational efficiency and expediency in execution of projects and delivery of service
- d. bring in customer oriented approach in service delivery and benchmark service levels
- e. and finally to create competitive environment within this sector.

- 1.1.3. The State Government brought a separate Public Private Partnership Policy during 2012, vide G.O 538/XXVI/2(15)/2011. In the current scenario with the change in guidelines by the Department of Economic Affairs, Government of India and considering developmental trends in the market, the need for formulating a new policy with updations in the institutional framework, structuring mechanism of the projects and other relevant updations has been felt essential.

This PPP policy declares in the first place an unambiguous support for the implementation of PPP projects and also takes care of their regulation and the position of the regulator in strengthening fiscal discipline.

In order to take full advantage of PPPs Government of Uttarakhand shall issue guidelines for subjecting all infrastructure projects, above a certain size in terms of project cost, to a PPP test. If the PPP test suggests that project would result in better value for money for the Government and all stakeholders though PPP then it shall be developed as a PPP project. Only in case PPP test indicates impossibility of PPP by way of negative value for money for Government through PPP then it shall be considered under full government funding.

1.2. PPP Definition

1.2.1. PPPs are an arrangement between the public entity and the private partner for development of infrastructure or delivery of services. Under conventional construction contracts, the private sector bears only the design and construction risk whereas under PPPs, they are likely to bear other risks pertaining to financing, demand, and operations, depending upon the risk sharing mechanism between the public entity and the private partner.

The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, has not limited the definition of PPPs to only infrastructure/ provision of related services, making it more exhaustive in scope and application to sectors. It defines PPPs as follows:

"A PPP means an arrangement between Government or statutory entity or Government owned entity on one side and a private sector entity on the other, for the provision of public assets and/or related services for public benefit, through investments being made by and/or management undertaken by the private sector entity for a specified period of time, where there is a substantial risk sharing with the private sector and the private sector receives performance linked payments that conform (or are benchmarked) to specified, pre-determined and measurable performance standards."

1.2.2. Government entity shall mean :

- Government Departments & Directorates
- Government sponsored boards, societies and other autonomous bodies
- Government sponsored education, research and knowledge management institutions
- Urban Local Bodies and Panchayats
- Government owned companies

Private Sector Entity shall mean an entity in which 51% or more of the subscribed and paid up equity is owned and/or controlled by a private entity. This shall include privately owned/sponsored societies, not for profit organizations as well.

1.3. Essential Conditions of PPPs

Based on the definition of PPPs by the Department of Economic Affairs, Government of India; the essential conditions that define PPPs are as follows:

Arrangement with private sector entity:	The asset and/or service under the contractual arrangement will be provided by the private partner to the users. The arrangement enables the private sector to provide a public asset and deliver the service and sets out the mechanism for sharing of risks and rewards. An entity that has a majority Non-Governmental ownership, i.e., 51 percent or more, is construed as a private sector entity.
Provision of public asset or service for public benefit:	In PPPs, only those facilities/services are transferred to the private partner which generally are hitherto provided by the Government as a sovereign function, to the people. For better understanding:

	<p>"Public Services" are those services that the State is obligated to provide to its citizens or where the State has traditionally provided the services to its citizens.</p> <p>"Public Asset" is that asset the use of which is inextricably linked to the delivery of a Public Service, or, those assets that utilize or integrate sovereign assets to deliver Public Services."</p>
Investments being made by and/or management undertaken by the private partner:	Financial investments by the private partner may not be a necessary condition for PPPs. An arrangement where only private sector efficiencies are being harnessed for better delivery of services without any investments by the private partner can also be classified as a PPP.
Time Period:	The arrangement will need to be for specified time period. There can be no PPP arrangements that go on for perpetuity. The arrangement between the parties (the expires at the end of such a specified time period, unless it is extended mutually as per pre-specified contractual conditions.
Risks Sharing:	Sharing of risks is the prime feature of PPP arrangements. PPPs are frameworks where the risks are allocated to either the private partner or the public entity, whichever is best suited to manage and mitigate it. Every PPP arrangement will need to set out the allocation of risks between parties (the parties refer to the public entity and the private partner that enter into a PPP arrangement) for the specified time period.
Performance linked payments:	PPP arrangements feature payments that are made from one party to another as consideration for the arrangement. The quantum of these payments primarily depends on the quality of service delivery and performance and not merely on provision of an asset/facility.
Conformance to performance standards:	A strong focus is on service delivery by the private partner and compliance to pre-determined as well as measurable standards that are specified by the public entity.

Only those arrangements between public entity and private partner which satisfy all the above essential conditions are termed as PPPs. While designing a project, Head of the Administrative Department will decide if the project fulfill above conditions and can be considered as PPP or not.

1.4. Applicability

1.4.1. This PPP Policy shall apply to all Infrastructure Projects including social sectors, Primary sectors and service industry implemented through Public Private Partnership in the sectors as may be notified by the Government or Government Entity as define in para 1.2.2 under the Policy from time to time. This Policy would apply to all state government entities as defined in 1.2.2.

1.5. The Policy Objectives

1.5.1. The key objectives of this policy are to: -

- 1.** Create a conducive environment for private investment so as to:
 - a.** Find additional capital from private sector to fund commercially viable projects and thus freeing of government funds for better allocation to commercially nonviable but socially justifiable projects
 - b.** Utilize efficiencies from innovativeness, flexibility, cost efficiency, alternative management and implementation skills of private sector
 - c.** Provide and ensure better quality value added services to the consumer and the public at large
 - d.** Provide better identification of needs and optimal use of resources
 - e.** Develop efficient public infrastructures in shorter terms than otherwise
- 2.** Achieve economic growth and boost direct international and domestic investments by giving incentives to private investment in public infrastructure and public services
- 3.** Limit negative impact of non-systematic execution of PPP projects
- 4.** Set up a transparent, consistent, efficient administrative mechanism to create a level playing field for all participants and protect interest of all stakeholders.
- 5.** Prepare a shelf of projects to be offered for PPP with assistance of the owner departments and take them forward through a transparent selection process.
- 6.** Provide necessary risk sharing framework in the project structure so as to assign risks to the entity most suited to manage them.
- 7.** Put in place a mechanism to ensure the improved value for money assessment of all projects to ensure the incremental benefit to public by selecting right projects for public private partnership.
- 8.** Put in place an effective and efficient institutional mechanism for speedy clearance of the projects.
- 9.** Create a robust dispute redressal mechanism / regulatory framework for PPP projects.

1.6. Priority Sectors

1.6.1. The priority sectors covered by the policy, which may be modified from time to time, are as follows:

Sr. No.	Sector	Sub Sector
1.	Urban	a. Urban Transportation Systems / Improvement of Public Transport Facilities including construction of state-of-the-art bus-stands. b. Solid waste Management c. Sewerage & Drainage d. Mass Rapid Transport Systems e. Water treatment and Supply f. Any component under Smart City Mission
2.	Energy	a. Hydro Electric Power, Transmission and Distribution Systems b. Renewable Energy Generation and Distribution
3.	Agriculture & Rural Development	a. Horticulture and Floriculture b. Organic Farming and Indigenous seed development c. Agriculture Productions and Marketing d. Rural Infrastructure e. Water treatment and Supply
4.	Transport	a. Airports, Airstrips and Heliports b. Roads, Bridges, Bypass and Ropeways c. Railway & related projects d. Inland container depots and logistics hubs
5.	Tourism	a. Tourism and related infrastructure including recreational b. Destination Development c. Eco-tourism
6.	Social	a. Healthcare infrastructure and Health Secondary & Tertiary care services b. Education infrastructure and related services
7.	Trade & Industry	a. Industrial parks, Theme Parks like Information Technology (IT)/ Bio- Technology (BT) Parks, Knowledge Parks, Special Economic Zones and Townships b. Trade fair, convention, exhibition, and cultural centers

Any other sector / facility as may be included by the Government

1.6.2. PPP test

All the infrastructure projects mentioned in (para 1.5.1) above shall be subject to PPP test to ensure better value for money for the Government and Stakeholders

2. PPP Process

State Government wants to promote more Projects in PPP mode and so new robust mechanism is proposed:

Stage 1

- a. Project Identification Stage:
 - i. Expression of a Need
 - ii. Need Analysis
 - iii. Options Analysis
 - iv. Pre-feasibility studies

Stage 2

- a. Activities Post Identification of Project
 - i. Hiring Advisors/Consultants
 - ii. Stakeholder Consultation
- b. Project Feasibility Stage
 - i. Preparation of Technical Feasibility Report
 - ii. Preparation of Financial Feasibility Report
 - iii. Value Proposition of Projects
 - iv. Economic Feasibility
 - v. Adherence to the Legal Compliance Framework
- c. Project Structuring Stage
 - i. Risk Analysis
 - ii. Indicative Contractual Framework
- d. Pre-Procurement Activities
 - i. Land Acquisition if any required
 - ii. Shifting of Utilities if any required
 - iii. Study of Approvals and Clearances required and also to apply for the same
 - iv. Inter-departmental coordination
- e. Bid Documentation Stage
 - i. Request for Qualification
 - ii. Request for Proposal
 - iii. Project Information Memorandum
 - iv. Draft Agreement
- f. Procurement Process
 - i. Competitive Procurement Strategy like roadshow
 - ii. Single Stage or Two Stage bid process
 - iii. Selection of private partner
- g. Post Award Contract Management
 - i. Contract Management framework
 - ii. Formation of Contract Management Team

Apart from above, in order to attract maximum private players attention, Department/Agencies will also upload details of upcoming PPP Projects in <https://investuttarakhand.com> of Industry Department, Government of Uttarakhand.

3. CORE PRINCIPLES

3.1. Core Principles

This policy is guided by following core principles

- a. Value for money assessment
- b. Efficient use of existing assets and optimal allocation of additional resources
- c. Payment for services
- d. Equitable contractual structures
- e. Transparent process of procurement
- f. Fair regulatory framework
- g. Enabling institutional frameworks
- h. Sustainable incentives and concessions

3.2. Value for money assessment

GoUk shall encourage all departments/ agencies to inculcate the spirit and process of value for money assessment of all projects into their internal working so as to create a better benchmarking of bids for PPP projects.

Each sector and project would have different requirements with regard to value for money assessment but main principles would be to ensure better utilization for resources, better allocation of risk and thereby creating a better value to public at large for the output services.

3.3. Efficient Use of Assets and Allocation of Resources

In order to achieve the best possible use of resource pool available to government and to minimize the gestation periods for the planned benefits from new services, government first must look at the ways to improve efficient use of existing assets and create possibility of better management of service delivery through them.

This would then lead to right prioritization of resource allocation, to create newer assets through public private partnership process. This will also lead to better project formulation, which would bring in integrated infrastructure development approach by integrating the existing and new assets.

GoUk would encourage development of projects based on social need and economic viability. GoUk, however, recognizes that all "social" projects may not offer sufficient commercial incentive for PPP. In such cases, Government would use other compensation mechanisms like provision of VGF, or annuity or modified annuity payments. As an alternative, GoUk (or Government Agency) may implement such

projects upfront and eventually transfer management of services to a Private Sector Participant (PSP), wherever feasible.

GoUk would also develop objective criteria for rationalization of investments for expanding, upgrading and/or development of Infrastructure. Typically, project identification and prioritization would be governed by the following considerations:

- a. Magnitude of gap between demand and supply for the Infrastructure;
- b. Focus on balanced regional development, especially with regard to provision of basic Infrastructure;
- c. Development of physical/ inter-sectoral linkages where significant economic gains can be realized.

Since GoUk would actively promote PPP in Infrastructure Projects, a larger share of investable public funds could be used for social needs that may not otherwise be amenable to private finance initiatives. In order to create a sustainable source of government funds for long-term infrastructure financing, GoUk would leverage internal and extra-budgetary resources under various schemes of GoI and bilateral and multilateral agencies.

3.4. Payment for Services

3.4.1. GoUk recognizes that in a system where pricing of services is not economically sustainable, users would have no incentive to economize on their use of resources, and service providers would have no incentive to become more efficient. GoUk believes that the inculcation of the “provider-charges” and the “user-pays” principles is fundamental to the success of PPPs. To this end, GoUk would, where necessary and appropriate, consider levy of user charges (tolls, fees, tariffs, cesses etc.) to meet the following objectives:

- a. Create a stable and dedicated financial source for construction/ redevelopment/ rehabilitation/replacement of project assets and their ongoing operations and maintenance in order to provide efficient, sustainable and high quality services at affordable prices to users.
- b. Manage demand
- c. Encourage PPP
- d. Cover costs of service provision
- e. Recognizing that economically weaker sections may require certain subsidies in user charges, provide explicitly for such subsidies to the project, to ensure that the project remains economically viable.

3.4.2. The levy of user charges would be based on one or more of the following criteria:

- a. Savings to users
- b. Willingness to Pay
- c. Capacity to pay
- d. Need for explicit subsidies
- e. Uniformity between various projects
- f. Present service level and the improvement envisaged.
- g. Cost Recovery
- h. Debt service & Equity returns

3.5. Contractual Structures

3.5.1. GoUK would set in place appropriate contractual arrangements to give effect to the process of project implementation. GoUK's endeavour would be to develop contractual frameworks that would allow for equitable allocation of risks between the contracting parties, taking into account the legitimate concerns of private investors. The attempt would be to allocate risks to the party best suited to bear the risks.

3.5.2. Existing Assets: The contractual/ implementation structures used would include the following:

- a. Management of the whole or part of the assets by private operators through
 - i. Operations and Maintenance (O&M) contracts for pre-determined periods
 - ii. Lease of assets
 - iii. Rehabilitate, Operate, Maintain and Transfer (ROMT) contracts

3.5.3. New Assets: Depending on the nature of the project, the contractual structures/ agreements used for new projects would include inter-alia:

- a. Build & Transfer (BT)
- b. Build-Lease-Transfer (BLT)
- c. Build-Transfer-Operate (BTO)
- d. Build-Operate-Transfer (BOT)
- e. Build-Own-Operate-Transfer (BOOT)
- f. Build-Own-Operate (BOO)
- g. Build-Operate-Share-Transfer (BOST)
- h. Build-Own-Operate-Share-Transfer (BOOST)
- i. Build-Own-Lease-Transfer (BOLT)
- j. Design- Build-Finance-Operate-Transfer (DBFOT)
- k. Rehabilitate-Finance-Operate-Transfer (RFOT)

3.5.4. Special Purpose Vehicle (SPV)

Wherever appropriate, GoUk/ GoUk Agencies may participate in the equity structure of any SPV for the development and implementation of infrastructure projects. The selection of the PSP for participating in the SPV would follow the procurement process set out by GoUk. The equity structure of the SPV would be decided on a case-to-case basis.

3.6. Procurement Process

3.6.1. Primarily all PPP contracts would be awarded on the basis of a transparent competitive bidding process, under the ambit of the Uttarakhand Procurement Rules 2017.

In all cases, the award criteria would be spelt out upfront. The stages in the procurement process could be single-stage or two-stage, depending on the size or level of complexity of the project and also to encourage competitive bidding.

Guidelines shall be issued for handling single bid and speculative bids.

3.6.2. For this purpose, GoUk may use the services of suitably qualified independent advisers with the requisite technical knowledge empanelled by Government of India and Government of Uttarakhand. Generally, the stages in the procurement process would include:

- a. In principle approval of the project
- b. Expressions of interest (EOI)/ Request for Qualifications (RFQ)
- c. Approvals of RFP and DCA
- d. Request for Proposals (RFP)
 1. Technical and financial proposals
- e. Technical and Financial evaluation of bids
- f. Selection of PPP Partner(s)
- g. Signing of Agreements

3.6.3. The initial selection criteria would be based on the following pre qualification parameters

- a. Financial strength of the bidder - net worth, average turnover over past three years, asset base etc
- b. A minimum number of full time skilled employees
- c. Relevant Quality certification (ISO 9000, ISO 14000 etc)

- d. Should have undertaken a minimum number of projects (of specified value) in that sector.
- e. Track record of successful completion of projects in that sector

3.6.4. The criteria used for selection would include objective technical/ financial parameters, such as:

- a. Level of service, quality of assets offered;
- b. Lowest present value of Viability Grant support
- c. Lowest quantum of land
- d. Lowest present value of asset based support from the Government;
- e. Highest share (or present value of) of revenue;
- f. Lowest unit value or present value of payments by GoUk;
- g. Highest upfront payment (or present value of upfront payments);
- h. Highest present value of future payments;
- i. Lowest concession period;
- j. Lowest unit value or present value of user fees;
- k. Highest premium on (or present value of) equity shares offered.
- l. Best Value for Money proposed
- m. Lowest Annuity
- n. Lowest Modified Annuity

3.7. Regulatory Framework

GoUk recognizes that creation of Infrastructure under the PPP model requires that there be reasonable assurance that competing facilities would not be created that would materially adversely affect the technical and financial viability of the project. With this background in mind there would also be a responsibility for the government to ensure independent regulation of such monopolistic situations to ensure that the interests of both users and service providers are kept in view.

GoUk intends to set up independent regulatory authorities for some of the infrastructure sectors. The role of the regulator would include setting norms for entry and exit, tariff fixation, establishing standards for construction, operations and maintenance for the facilities/ services, revenue sharing between Private partner and Government agency, strengthening the exit barriers - in terms of fixing bank guarantees, collateral or any such instruments to avoid unilateral exit of private partner during the project term.

However, the setting up of the regulatory authorities would be decided based on the specifics of each sector.

3.8. Institutional Arrangement

The Government of Uttarakhand recognizes the requirement for an effective and efficient institutional mechanism and therefore constitutes the requisite committees and empowered groups for furthering the objectives of the Policy.

3.8.1. Expenditure Finance Committee (EFC)

Government of Uttarakhand shall constitute Expenditure Finance Committee (EFC) consisting of a group of Secretaries under the Chairmanship of the Chief Secretary, Government of Uttarakhand for facilitating infrastructure development in the State under PPP. State Nodal Officer PPP, Principal Secretary Planning/ Secretary Planning, shall be the member- secretary of EFC. All PPP Projects as mentioned in para 4.1.4 and 4.1.5 will require approval of EFC.

3.8.2. Role of the EFC

The EFC shall be the nodal agency to co-ordinate all efforts of the State Government regarding development of infrastructure sectors, involving private participation and funding from various sources.

3.8.3. Powers and Functions of the EFC

The Powers and Functions of the EFC would include:

- a. To prioritize, approve projects, sanction and authorize expenditure for PPP Projects.
- b. Recommend to State Cabinet approval of the projects mentioned in para 4.1.4 and 4.1.5
- c. To coordinate the efforts of other departments for the furtherance of the objectives of this Policy.
- d. To inspect, visit, review and monitor any PPP Projects regarding its implementation, execution, operation and management.
- e. To recommend en-action of special legislation for formation of appropriate regulatory mechanism, robust grievance redressal mechanism as may be required for the project.
- f. Frame and issue guideline to the line departments undertaking PPP initiatives
- g. Provide Technical Assistance to the departments for effective implementation of PPP projects
- h. EFC would be the driver for policy, regulatory and any relevant changes
- i. Create awareness on PPP initiatives among departments, private sector, citizens etc
- j. Approve specific service levels for the Private Partner in consultation with the project initiating department and ensure formulation of Service Level Agreement (SLA) between the Private Partner and project initiating department.

- k. Review progress of projects/ programmes undertaken under PPP and analyse the achievements with respect to the targets, both financial & physical and decide on corrective actions, if required
- l. Ensure appropriate capacity building initiatives are undertaken at various levels for successful execution of PPP Projects.
- m. Ensure development and roll out of appropriate communication strategies for State PPP Initiatives
- n. Ensure appropriate auditing and monitoring standards are developed and maintained in order to ensure highest standards of transparency and accountability.
- o. To constitute, from time to time, any committees/sub-committees from amongst its various experts/members and/or staff of the Society (PPP Cell) and assign specific responsibilities.
- p. Post award of Contract to Private Party, EFC will also monitor the progress of Project through PPP Cell and will ensure that Private Partner has received all Clearances through Single Window Clearance Route in timely manner.

3.8.4. PPP Cell and the Technical Secretariat

The EFC shall be assisted by a PPP Cell in the Planning Department in undertaking the functions specified under this policy & shall be under the direct supervision of Chief Secretary.

The PPP Cell is to be assisted by a Technical Secretariat and other Infrastructure project development entities floated by the state government.

The PPP Cell may also engage consultants as and when necessary. The engagement of Consultants would be from Uttarakhand Centre for Public Policy & Good Governance. The PPP Cell will be the nodal agency to receive the proposals in respect of the PPP projects and place them before the EFC and Cabinet for consideration and approval.

PPP Cell would set out the process for scrutinizing and clearing all investment proposals, assist in framing guidelines for assessing the feasibility of private investment, set in place standard procurement documents and framework agreements, and assist the Government/ Government Agencies in the procurement of developers.

PPP Cell would also facilitate the Government/ Government Agencies, to develop and implement Infrastructure Projects in the PPP format, in an expeditious manner.

PPP Cell would also help GoUK in formulation, implementing and monitoring all Externally Aided Projects functioning in the state.

The fund requirements for furthering the objectives of the Policy through the PPP cell shall be initially met through budgetary support.

3.8.5. Functions of the PPP Cell and Technical Secretariat (TS)

The Functions of the PPP Cell and its Technical Secretariat would include:

- a. To identify, conceptualize and create a shelf of projects in consultation with the owner department/agency
- b. Identify critical projects in different sectors that need immediate attention;
- c. Identify projects where significant benefits of network extension can be exploited for integrated infrastructure development
- d. To develop internal evaluation guidelines in consultation with the help of respective departments /agencies to evaluate and assess the projects under value for money principle to decide whether the projects are to be funded by the State Government through multilateral /bilateral funding and/or implemented with Private Sector participation.
- e. To recommend approval of such projects for PPP to the EFC & Cabinet.
- f. To assist different government departments/agencies in preparing pre-feasibility reports, Detailed project reports by itself or through consultants.
- g. To appoint / select consultants to take the projects upto selection of developer stage in consultation with the concerned department/agency.
- h. To interact with the Planning Commission, Government of India (GoI) and other funding agencies like World Bank to mobilize VGF and any other fund created for such purpose.
- i. To recommend the requirement of multilateral/bilateral funding for furthering the objectives of the Policy.
- j. To act as the nodal agency for capacity building for PPP in the state. To further this function it shall conduct/recommend exposure visits and training programs on PPP at various levels of government.
- k. To recommend appropriate regulatory mechanism / robust grievance redressal mechanism as per requirement of the project.
- l. To recommend requirements of PPP from UIDF for development of projects, gap funding and for any other requirement for furthering the objectives of this Policy.
- m. Formulation and recommendation of any legislation if required for creation, administration and monitoring of the Fund.
- n. To act as the knowledge repository for PPP in the state.
- o. GoUK also recognizes the role of public opinion and stakeholder participation in facilitating Infrastructure Project development and implementation. Since the viability of projects is contingent upon cost to the final user, it is important to ascertain "what the market can bear". Mobilizing public opinion and ensuring stakeholder participation is thus an integral part of Infrastructure Projects. PPP cell would collaborate with professional bodies, NGOs, Industry Associations, and User Groups in facilitating this process.
- p. Identify and resolve bottlenecks in the institutional framework that are likely to

impede investments and therefore provide a conducive environment for infrastructure development through PPP;

- q. Facilitate the conversion of approved projects into the implementation phase.
- r. To develop a robust monitoring framework for all PPP and EAP projects in the state and implement monitoring.
- s. Based on the strategy developed for each sector, PPP cell, in consultation with GoUK Departments/ Agencies, would prepare a road map for infrastructure development in the State

3.8.6. Creation of PPP Cell in Line Departments

PPP Cells shall be set up in all line departments/agencies to co-ordinate with the State PPP Cell and to take forward the PPP initiatives.

3.8.7. Creation of PPP Cell/ Committee District Level

GoUK shall set up a District PPP Committee at the District level, to co-ordinate and facilitate the implementation of infrastructure projects, including facilitation for obtaining clearances and approvals on a PPP route.

The District PPP Committee shall be chaired by the Collector of the concerned district. If required the District Committee may invite officers of appropriate rank, nominated by GoUK, as well as upto 3 representatives from the private sector, nominated by state level industrial forum.

4. PROJECT APPROVAL PROCESS

4.1. Project Approval Process

The Administrative Department undertaking the PPP Projects will have to follow the following Project Approval Process before inviting any Financial Offers from the prospective/ shortlisted bidders :

4.1.1. In Principle Approval for all Projects Developed in PPP Mode

The Administrative Department after completing Stage 1 activities mentioned in Section 2 of this Policy will send the proposal to PPP Cell for their initial comments and discussion. Based on the discussion a preliminary project report (PPR) will be drafted. The PPR will have indicative provision regarding various expenditures/studies/consultancy etc which will be required for Stage 2 process.

Post this, Administrative Department shall obtain necessary approval from appropriate authority. Moreover, during Stage 2 activities Administrative Department along with their Consultant will work closely in consultation with State PPP Cell.

Any Administrative Department which has sufficient capacity to provide information as per Annexure I-IV of Uttarakhand Procurement Rules, 2017 need not follow the Stage 1 procedure and can go directly to Stage 2 procedure.

All the proposals will be sent only after the approval of Competent Authority of the Administrative Department as per rules of business.

4.1.2. For PPP Projects with Project Cost of upto Rs Five Crores

- a. PPP Projects with Project Cost of upto Rs 5.00 cr has to be approved by a Finance PPP Committee headed by Principal Secretary/Secretary Finance with following members:
 - Principal Secretary/Secretary Planning or any Officer nominated by Principal Secretary /Secretary Planning but should not be below the rank of Additional Secretary
 - Additional Secretary Finance dealing with concern Administrative Department
 - PPP Expert
 - Secretary of the Administrative Department
 - Head of Department
- b. Representative of Administrative Department has to make presentation of the Project to above mentioned Committee.
- c. This will also be final approval from Finance Department and no further approval from Finance is required.

4.1.3. For PPP Projects with Project Cost of Rs Five Crores or more but less than Rs Fifty Crores, the Administrative Department shall obtain approval from following authorities :

- a. For PPP Projects with Project Cost of Rs 5.00 cr or more but less than Rs 50 cr has to be approved by Expenditure Finance Committee (E.F.C.) headed by Chief Secretary with following members:
 - Principal Secretary/Secretary Finance
 - Principal Secretary/Secretary Planning
 - Principal Secretary/Secretary Public Works Department
 - Principal Secretary/Secretary Tourism
 - Principal Secretary/Secretary Health
 - Principal Secretary/Secretary Law
 - Principal Secretary/Secretary of the Administrative Department (By Invitation only)

4.1.4. For PPP Projects with Project Cost of Rs Fifty Crores or more, the Administrative Department shall obtain approval from following authorities :

- a. Expenditure Finance Committee (E.F.C.) in accordance with the extant relevant procedure.
- b. Administrative Department shall take approval from the Competent Authority on basis of EFC and then will take it to Cabinet.
- c. The State Cabinet shall grant final approval on the Project.

4.1.5. Summary of Project Approval Process

A. For PPP Projects Developed by GoUK

Project Cost of PPP Projects (Rs Crores)	In Principle Approval	Approval from Finance PPP Committee	EFC	State Cabinet
Upto Rs 5 cr	Yes	Yes	No	No
Rs 5 cr or more but less than Rs 50 cr	Yes	No	Yes	No
Rs 50 cr or more	Yes	No	Yes	Yes

4.1.6. Definition of Project Cost

For the purpose of this section 3.1.6 A, Project Cost shall include

- Revenue Generating Commercial Projects :** Project Cost shall include the value of estimated capital investment on civil construction, procurement of equipments, furniture, fixtures, vehicles or any other equipment, physical asset required to be installed or procured for the Project, project development expenses, financing and other incidental charges.or
- For Operation & Maintenance Project:** Estimated present value of the revenue to be earned by Concessionaire in first full year of operation
- Non revenue Generating Projects, Efficiency enhancement/ cost savings projects (management or service contracts or engineering, performance based O&M contracts and Annuity or Modified Annuity Based contacts) :**

Project Cost shall include :

- the value of estimated capital investment by the Private to be incurred on civil construction, procurement of equipments, furniture, fixtures, vehicles or any other equipment, physical asset required to be installed or procured for the Project, project development expenses, financing and other incidental charges AND/ OR
- Estimated present value of grant (capital/ revenue), annuity payable by the Government to the private partner throughout the Concession Period.

4.2. Urban Local Bodies and Gram Panchayats etc.

- a. Urban Local Bodies (ULB's) shall take approval from their respective boards and forward the Proposal through their Administrative Department such as Urban Development Department and shall follow project approval process as per Clause 4.1 of this Policy.
- b. Rural Local Bodies (RLB's) shall take approval from their respective boards of Panchayats and forward the Proposal through their Administrative Department such as Panchayati Raj and shall follow project approval process as per Clause 4.1 of this Policy.

4.3. Government owned companies, institutions, joint ventures etc.

- a. These independent government entities shall not be allowed to bypass the prescribed approval process in this policy

4.4. Approval Process for Projects developed under PPP Mode.

Since the PPP Project development process is a technical subject and complex evaluation procedures for project structuring are involved, the concerned Principal Secretary/ Secretary may identify officers having requisite technical and project management expertise for undertaking PPP Project development process, scrutiny and appraisal both at Head of Department and Secretariat level.

4.5. Approval of Developer

The final approval on the selected Concessionaire may be obtained from the concerned Minister by the Administrative Department.

4.6. Development through Special Purpose Vehicles (SPVs)

SPVs shall be formed as and when required to carry forward and realize the objectives of this Policy and get various clearances and permissions in the SPVs to speed-up the project.

5. MONITORING, EVALUATION AND ASSESSMENT FRAMEWORK

For an effective implementation of the PPP program, a robust monitoring, evaluation and assessment framework would be developed and put into place.

5.1. Monitoring & Evaluation (M&E)

Under the M&E framework, the line departments would be responsible for project design and timely implementation under each of the respective PPP project. The PPP Cell /Technical Secretariat at the state level will be responsible for the overall monitoring and evaluation of all projects in the State.

Planning Department will review and monitor the progress of PPP projects regularly. All the Departments / Agencies carrying out PPP projects will provide information/data to the PPP Cell regarding the latest development.

The key roles to be undertaken under M&E by PPP Cell in this regard are discussed below:

5.1.1. Project monitoring

Under the project monitoring, the key roles to be undertaken by the PPP Cell and Technical Secretariat would include:

- a. Identify and design programme monitoring tools in the form of standard documents, spreadsheets and project plan templates.
- b. Support development of capacity building guidelines for departments and project teams in the field of M&E.
- c. Ensure financial and physical monitoring of individual projects, track deviations and identify key action areas for resolution.
- d. Setting up and administration of a process for reporting progress on key project metrics. For this the PPP Cell and Technical Secretariat may need to enrol an agency for rolling out the M&E framework.
- e. Setting up process for facilitating documents for review/ sign-off of all the projects under PPP initiatives of the State.

5.1.2. Project evaluation and impact assessment

Under the project evaluation and impact assessment the key roles to be undertaken by the PPP Cell and Technical Secretariat would include:

- a. Support development of capacity building guidelines for departments and project teams in the field of project evaluation and impact assessment.
- b. Ensure that individual project evaluation and impact assessment is undertaken for all projects.
- c. Preparing and circulating a project reference guideline for participating departments in topical subjects such as drafting Service level agreements, etc.
- d. Setting up process for facilitating project evaluation and impact assessment which will include enrolment of consultants/ organizations for carrying out project evaluation and impact assessment and engaging third party for data collection, base-lining and assessing performance

6. RISK ASSESSMENT FRAMEWORK

Risk is the potential for unwanted happenings which could impair the achievement of Project objectives and outputs. A robust risk assessment framework would be put in place that could assist State PPP initiatives in undertaking adequately and timely assessment of risks and ensuring that appropriate risk mitigation measures are adopted. GoUk shall issue guidance notes on generic risks from time to time.

7. STATE SUPPORT

The State Government will formulate sector specific policies wherever required for providing specific incentives and also establish mechanism for tariff setting, pricing, arbitration, safety and operational standards etc. It also envisages coordination across infrastructure sectors and dovetailing of sectoral plans.

State Support would include:

7.1. Administrative Support

State Government shall offer necessary administrative support to all the infrastructure projects developed in the State, which would include:-

- a. To facilitate obtaining all State & Central Government clearances as may be required for the project.
- b. To facilitate all rehabilitation & resettlement activities in case so required as per Rehabilitation and Resettlement Policy of the State Government including shifting of utilities wherever required.
- c. To facilitate the process of availing benefits under various Central Government and State Government schemes (as may be applicable) to enhance the viability of projects under implementation;
- d. To facilitate provision of supply of power and water at projects site.
- e. To facilitate acquiring of land necessary for the project.

7.2. Financial Support

Projects may be bidded on the basis of Financial Support required from the GoUk/GoUk agency. Such a financial support may be in annual lump-sum payments, performance linked payments and shall be funded by the budgetary allocations made by GoUk/GoUk Agency.

In addition to the viability gap funding available under different schemes of Government of India, the State Government may also contribute for the remaining portion of Viability Gap as emerged from the open bid in cash or through other concessions to help the emergent infrastructure projects attain viability and get implemented.

8. PROTECTION OF STAKEHOLDER RIGHTS

The rights of the users, developers, the local community and lenders, together referred to as stakeholders shall be protected. The various mechanisms considered may include:

- a. Providing adequate legislative and administrative support for successful and timely implementation and operation of the project while safeguarding the interest of local communities.
- b. Providing adequate legislative and administrative support for levy and collection of user charges.
- c. Adopting, adapting and developing MCAs and incorporating in all project documents the requisite clauses for protection of the rights of all stakeholders.
- d. Structuring of concession agreements incorporating service standards, revenue streams and levy of equitable user charges also providing for exempt category of users wherever applicable.
- e. Setting up of Independent Regulators appellate forums and other robust dispute redressal mechanism.
- f. Ensuring that stakeholder consultations are made primary requirement in project approval requirements.
- g. Providing timely information under Right-to-Information Act

9. DURATION AND REVIEW OF POLICY

This policy would come into force with effect from the date of issue of Government Order and would be effective till the formulation of a new PPP policy.

There would be a review of this Policy based on a critical assessment of feedback from stakeholders, and changes in scope that are deemed necessary and desirable, would be incorporated at that stage.

The government recognizes that expanding and institutionalizing the scope of PPP in provision of infrastructure may also necessitate appropriate changes in the existing legislative framework. The specific legislative constraints for PPPs would also be reviewed and addressed during the review.

Note:- In case of contradiction with the provision of any act/rule/Sub-rule/regulation in forces in this policy, the provision of that related act/rule/Sub rule/regulation shall be effective but in the event of having hindrance in developing and executing the PPP proposal due to such provision, the proposing administrative department shall obtain a waiver as required under the relevant act/rule/Sub rule/regulation from the competent authority.

ORDER : Ordered that the Resolution be published in next extraordinary issue of the Uttarakhand Gazzette and copies thereof be forwarded to all Departments of government, all Heads of Department and Accountant General Uttarakhand.

By order of the Governor

MAJOR YOGENDRA YADAV,

Additional Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अगस्त, 2020 ई0 (श्रावण 24, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

July 27, 2020

No. 3296/UHC/Admin.(A)/2020--Certified that in pursuance of the Order No. DG-Ek-101-2016 Dated 23.07.2020 of Inspector General of Police, Personnel Uttarakhand, the undersigned has taken over the charge of the office of the Superintendent of Police, Vigilance Cell in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital in the Afternoon of 23.07.2020 as the undersigned has promoted from the post of Additional Superintendent of Police, Grade-1 (in Level-12 of Pay Matrix, Pre-revised Grade Pay Rs. 7600) to the post of Additional Superintendent of Police, Special Grade (in Level-13 of Pay Matrix, Pre-revised Grade Pay Rs. 8700).

AMIT SRIVASTAVA-II

Countersigned,

HIRA SINGH BONAL,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

कार्यालय-डा० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

विज्ञप्ति

23 जुलाई, 2020 ई०

पत्रांक 1031/चार-43/2019/टी०सी०यू०-डॉ० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2012 के आधार पर चयनित पुलिस उपाधीक्षकों हेतु दिनांक 13, 14 व 15 जुलाई, 2020 को विभागीय परीक्षाओं का आयोजन किया गया।

विभागीय परीक्षा (पुलिस उपाधीक्षक), 2020 में सम्मिलित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में इस विज्ञप्ति के द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण किये गये विषय					
1.	श्री अंकुश मिश्रा	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
2.	श्री अविनाश वर्मा	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
3.	श्री अनुज	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
4.	सुश्री पल्लवी त्यागी	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
5.	श्री विवेक कुमार	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
6.	श्री नरेन्द्र पन्त	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
7.	श्री अनुज कुमार	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
8.	सुश्री पूर्णिमा गर्ग	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
9.	श्री दीपक सिंह	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
10.	सुश्री जूही मनराल	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
11.	सुश्री वन्दना वर्मा	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
12.	श्री आशीष भारद्वाज	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
13.	श्री शान्तनु पाराशर	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
14.	सुश्री दीपशिखा अग्रवाल	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
15.	श्री अमित कुमार	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
16.	सुश्री संगीता	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI
17.	श्री तपेश कुमार चन्द	पुलिस उपाधीक्षक	I	II	III	IV	V	VI

विषय संकेत	विषय
I	Criminal Procedure Code
II	Indian Penal Code and Indian Evidence Act
III	Special Acts
IV	Police Regulation
V	Financial and Account Rules
VI	Hindi (Translation, Case Diary Reading)

राजीव रौतेला,
निदेशक।

कार्यालय जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड

कार्य भार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र

संख्या 02/जि0पु0शि0प्रा0/2020-21-उत्तराखण्ड शासन के गृह अनुभाग-1 संख्या- /XX-1-2020-7(14)2006 दिनांक 15 जुलाई, 2020 के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 17 जुलाई, 2020 के पूर्वाह्न में अध्यक्ष जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून के पद का कार्य भार ग्रहण कर लिया है।

के0डी0 भट्ट,

अध्यक्ष,

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग

आदेश

17 जुलाई, 2020 ई0

संख्या 120/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2020-सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट-3 दिनांक 18-08-2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0 पार्ट-3 दिनांक 17-11-2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रुद्रप्रयाग के रूप में मैं मोहित कुमार कोठारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रुद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ। उक्त अवधि में लाइसेन्स निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेन्स अवमुक्त किया जायेगा :-

क्र० सं०	चालक का नाम व पता	डी०एल० संख्या	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	दिनेश लाल पुत्र श्री सज्जन लाल ग्राम गांधारी पो० हरेथीखाल जनपद रुद्रप्रयाग पिन- 246171	UK13-20170012618 VALIDITY (NT) 07-10-2032	बाईक में ओवरलोड सवारी।	ARTO RUDRAPRAYAG	17.07.2020 से 16.10.2020
2	शुभम पुत्र श्री विजय लाल मकान सं० 37 ग्राम आमकोटी पो० पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल पिन- 246001	UK-1220150017210 VALIDITY (NT) 26-06-2039	वाहन संचालन के दौरान मोबाईल फोन का प्रयोग।	ARTO RUDRAPRAYAG	17.07.2020 से 16.10.2020
3	सुखदेव सिंह पुत्र श्री चंद्रमोहन ग्राम धारकोट जखोली जनपद रुद्रप्रयाग पिन- 246141	UK-1320180000916 VALIDITY (NT) 14-06-2038	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	17.07.2020 से 16.10.2020
4	संदीप रोगवाल पुत्र श्री कलीराम सेमवाल जनपद रुद्रप्रयाग पिन-246171	UK13-20180000081 VALIDITY (NT) 17-01-2038	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	17.07.2020 से 16.10.2020
5	मनि सिंह पुत्र श्री वीर सिंह ग्राम लेखला तहसील भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी पिन- 249193	UK-1020080002265 VALIDITY (NT) 26-08-2028 VALIDITY (T) 27-08-2020	ओवरलोड सवारी(भार वाहन)।	ARTO RUDRAPRAYAG	17.07.2020 से 16.10.2020
6	अनिता पत्नी श्री पृथ्वी सिंह रावत ग्राम लोली पो० बिरौन जनपद रुद्रप्रयाग।	UK-1320170012692 VALIDITY (NT) 19-08-2033	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	17.07.2020 से 16.10.2020
7	सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण चंद ग्राम व पो० धरमानाला पो० दूलासा तहसील भटियायाट जनपद चम्बा पिन- 176207	HP-5720130001349 VALIDITY (NT) 16-09-2033 VALIDITY (T) 28-03-2021	खतरनाक संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	17.07.2020 से 16.10.2020
8	महावीर सिंह रावत पुत्र श्री सिताव सिंह रावत 06 गढ़वाल राईफल्स C/O 56 ए०पी०ओ० देहरादून पिन- 248001	UA-0720110149255 VALIDITY (NT) 11-08-2026	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	17.07.2020 से 16.10.2020
9	महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बसंत सिंह डी-120 सेक्टर 15ए अजरौडा फरीदाबाद पिन- 121007	HR-5120160002356 VALIDITY (NT) 04-02-2033	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	17.07.2020 से 16.10.2020
10	जगमोहन पुत्र श्री हीरा लाल ग्राम सौरा रुद्रप्रयाग पिन- 246475	UK-1320180002079 VALIDITY (NT) 15-11-2038	वाहन संचालन के दौरान मोबाईल फोन का प्रयोग/तेज रफ्तार से वाहन का संचालन।	SP GARHWAL TEHRI	17.07.2020 से 16.10.2020

11	धर्मेश शर्मा पुत्र श्री आर0के0 शर्मा 1ए/7 गीता कॉलोनी पूर्वी दिल्ली पिन- 110031	DL-0719999244428 VALIDITY (NT) 12-09-2029	नशे की हालत मे वाहन का संचालन।	SP RUDRAPRAYAG	17.07.2020 से 16.10.2020
12	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री देवी प्रसाद ग्राम व पो0 खांखरा जनपद रुद्रप्रयाग पिन- 246171	UK-1320160010048 VALIDITY (NT) 09-02-2030	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	17.07 2020 से 16.08.2020

मोहित कुमार कोठारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अगस्त, 2020 ई0 (श्रावण 24, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

उपविधि

19 मार्च, 2020 ई0

पत्रांक: 2894-नगर निगम अधिनियम की धारा 541(1)(42) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली, 2016 के नियम 15 (ड), 15 (च) एवं 15 (यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम द्वारा ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए अपने क्षेत्राधिकार में लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित उपविधियाँ बनाई गयी है :-

अध्याय-1

सामान्य

- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख
- (1) ये उप-नियम नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2019 कहलायेंगे।
- (2) ये उप-नियम नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
- ये उप-नियम नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।
- परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू हैं:-

- (क) "बल्क उद्यान और बागवान कचरा" का अर्थ है, उद्यानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेड़ों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेड़ों की कटिंग, टहनियां, लकड़ी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेड़ों की छटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता है।
- (ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ है कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे बाद में यहा एस. डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;
- (ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुंचाना;
- (घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है नगर निगम के नगर आयुक्त, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।
- (ङ) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया है।
- (च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अन्तर्गत किया जाना है।
- (छ) "सामुदायिक कूड़ा घर (ढलाव)" का अर्थ है, नगर निगम द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सड़क किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;
- (ज) "कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर निगम या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;
- (झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर निगम के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर निगम द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर निगम या नगर निगम द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;
- (ञ) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया है;
- (ट) "फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) " का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती है। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है;
- (ठ) "कूड़ा-कचरा" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूड़ा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेंकना अथवा संग्रह करना इन उप-नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुंचाने की आशंका हो।
- (ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुंचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।
- (ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारों का इस्तेमाल करता है;

- (ग) "अधिभोगी/पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।
- (घ) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकड़े होते हैं; और उनके ईंधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हें रिफ्यूज डेराइब्ड ईंधन कहा जाता हैं।
- (ङ) "निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्ल्यूएम नियमों और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;
- (च) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नहीं;
- (छ) "संग्रहण" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;
- (ज) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर निगम के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियों को साफ करने के लिये नगर निगम/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;
- (झ) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल;
- (ञ) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी" का अर्थ है, नगर निगम द्वारा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सके;
- (ट) "खाली प्लॉट" का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;
- (2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय -2

ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

- (प) सभी कचरा उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रूप से पृथक् करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रूप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगा:-
- (क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा
- (ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
- (ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनों श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बों में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर निगम के निर्देशों के अनुसार पथ्यकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।
- (पप) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस कचरे को पृथक् करे और उसे संगृहीत करे निम्नांकित 3 वर्गों में:-
- (क) गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरा
- (ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
- (ग) उपयुक्त कूड़ेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एजेंसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रों या संग्रहण केंद्रों को सौंपेगा और उसके लिए को नगर निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।
- (पपप) पृथक् किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगा:-
- हरा:- जैव अपघटीय कचरे के लिए;
- नीला:- गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए;

काला:- घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(पअ) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर निगम के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक् किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौंपी जाए। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर निगम द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अ) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर निगम की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक् किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूड़ा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौंपेंगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर निगम द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अप) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर निगम के भागीदारी से, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक् किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेंगे और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौंपेंगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर निगम द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अपप) कोई व्यक्ति गैर-लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरूरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर निगम को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगर निगम द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सकें।

(अपपप) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबंधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए।

(पग) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानों में संग्रहित करेगा और उसे नगर निगम द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौंपेगा।

(ग) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर निगम के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(गप) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर निगम या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(गपप) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(गपपप) बायो मेडिकल कचरा, ई-कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(गपअ) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड़ कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पोल्ट्री, मछली और पशु वध संबंधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हें ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुंचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूड़ा घरों में डालना निषेध होगा।

(गअ) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निगम श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय-3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:-

(प) नगर निगम के सभी क्षेत्रों या वार्डों में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर निगम संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(पप) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर निगम वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(पपप) कचरे को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएंगे।

(पअ) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(अ) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(अप) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं दुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता है।

(अपप) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध है। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(अपपप) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर निगम द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो-टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होंगे। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उप-खंड(पअ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड़ कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(पग) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरूरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजों को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगे और उनमें जैव अपघटीय और गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(ग) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(गप) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा दुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएं और नगर निगम द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर निगम द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर निगम अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और दुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(गपप) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/ साइकिल रिक्शा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(गपपप) अत्यंत भीड़ भाड़ वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(गपअ) ऐसी छोटी, तंग और भीड़ी गलियों/लेनों में जहां थ्रीव्हीलर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(गअ) ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतों जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूड़ेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(गअप) नगर निगम या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अध्याय-4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा

(प) घरों में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूड़ा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(पप) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होंगे:-

(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरों का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा:-

☐ हरा: जैव अपघटीय कचरे के लिए

☐ नीला: गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए

☐ काला: घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर निगम समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(पअ) नगर निगम स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रों का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(अ) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर निगम या किन्हीं अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप-नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगों के होंगे।

(अप) संग्रहण केंद्रों का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(अपप) संग्रहण केंद्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

(अपपप) सभी आवास सहकारी समितियों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप-नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सकें।

(पग) नगर निगम या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूड़ाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(ग) सूखे कचरे (गैर-जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर निगम अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रूप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव उपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रों को स्थानांतरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते हैं अथवा अधिकृत एजेंटों और/या नगर निगम से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बेच सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते हैं। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

(गप) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहां निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमभव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर निगम अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रों पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय-5

ठोस कचरे की दुलाई

7. ठोस कचरे की दुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:-

(प) कचरे की दुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभांति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े। इन वाहनों में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते हैं, जो नगर निगम द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(पप) नगर निगम द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूड़ेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(पपप) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटों जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथेनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुँचाया जाएगा।

(पअ) जहाँ कहीं प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(अ) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रों अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुँचाया जाएगा।

(अप) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(अपप) नगर निगम कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(अपपप) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें।

(पग) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहाँ कहीं प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(ग) यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खड़े नहीं पाए जाएँ, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(गप) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(गपप) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।

(गपअ) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(गअ) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूड़ादानों से कचरा प्राप्त करेंगे।

(गअप) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो-टिप्परों, तिपहिया वाहनों, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रूट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएँगे।

(गअपप) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूड़ा करकट इधर उधर न फैले।

(गअपपप) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चाहिए।

(गअग) नगर निगम अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय-6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :-

(प) नगर निगम ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रों और सम्बद्ध ढाँचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा:-

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो-मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बड़े कम्पोस्टिंग/बायो-मिथेनेशन प्लांटों के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा आधारित बिजली संयंत्रों को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्ड ईंधन के रूप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रूप में ईंधन प्रदान करते हुए।

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(पप) नगर निगम रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(पपप) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधों की कार्यशर्तों का हिस्सा होगा।

(पअ) नगर निगम सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपड़ा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियों को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देश:-

(प) नगर निगम सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों एवं रेस्त्राओं, बैंकवेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(पप) नगर निगम यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(पपप) नगर निगम यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाए।

(पअ) नगर निगम कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान-

नगर निगम अवशिष्ट कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरूप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्ध ढांचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क:-

(क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर निगम द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट हैं।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर निगम के कर एवं राजस्व अनुभाग अथवा मेयर/नगर निगम द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर निगम इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर निगम ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढ़े पाँच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती तीनवर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँती वसूल की जायेगी।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंड :- (क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अधिशासी अभियंता, स्वास्थ्य निरीक्षक कर अधीक्षक, कर निरीक्षक, सब इन्स्पेक्टर, चौकी, थाना प्रभारी होंगे तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं महापौर सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूची 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 2 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

(ङ) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्व:-

(प) कूड़ा फेंकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फैलाना : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़ादानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूड़ा फैलाना : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूड़ा नहीं डालेगा।

(ग) वाहनों से कूड़ा फेंकना : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा नहीं फेंकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना : कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सके।

(ङ) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी : कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरों द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान : कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा।

(छ) नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम सीमान्तगत समस्त खाद्य पदार्थ विक्रेताओं (जैसे होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा इत्यादि) को स्वच्छता/सफाई से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(पप) कचरे को जलाना : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा।

(पपप) "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियाँ/गटर, सड़क किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(पअ) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शनियाँ, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियाँ, वाणिज्यिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनो और प्रदर्शनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर निगम से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

(अ) ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगर निगम द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधि में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल करदी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुँचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नहीं होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और दुलाई में नगर निगम की सेवाएँ प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हें नगर निगम के सम्बद्ध जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(अप) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर निगम निम्नांकित ढंग से निपटेगा :-

(क) नगर निगम किसी परिसर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएँ पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर निगम निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है :

(प) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेगा।

(अपप) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व

(क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैंड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर निगम को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर निगम इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैंड मालिकों को, जो गैर-जैव अपघटनीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हें ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैंड मालिक या विपणन कंपनियाँ इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादों में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिन्हें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के लिए लोगों को शिक्षित करेगी।

14. नगर निगम के दायित्व :

(प) नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीनें लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर निगम अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी-निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर निगम सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हों।

(पप) नगर निगम अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा।

(पपप) नगर निगम विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर बने पेशाबघरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैंडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानों की निगरानी रख सके।

(पा) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुव्यवस्थित बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर निगम जहां कहीं अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(अप) नगर निगम अद्यतन सड़क/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(अपप) नगर निगम सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जकों और अन्य हितभागियों को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(अपपप) नगर निगम कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करे। नगर निगम विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते हैं।

(पग) नगर निगम स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कहीं संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।

(ग) नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(गप) नगर निगम यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते हैं और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(गपप) नगर निगम कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(गपपप) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर निगम को रिपोर्ट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(गपअ) नियमित जांच : महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा है।

(गअ) नगर निगम अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वेब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(गअप) नगर निगम एसडब्ल्यूएम नियमों और उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाड़ी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(गअपप) पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा।

(गअपपप) नगर निगम एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किए गये हैं।

अध्याय-10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे महापौर, नगर निगम के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगर निगम अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र यानियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप-नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र स	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जज रुपये में)
1	प्रति परिवार सामान्य	रु० 60.00
	प्रति परिवार मलिन वस्ती	रु० 40.00
2	ढाबा	रु 100.00
3	रेस्टोरेन्ट	रु 300.00
4	पान स्टॉल/टी स्टॉल/ठेले	रु 50.00
5	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस 20 बेड तक	रु० 300.00
	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस 20 बेड से अधिक	रु० 600.00

इस्तेमालकर्ता शुल्क(यूजर चार्ज)/प्रभार का भुगतान नगर निगम द्वारा अधिकृत संस्था/कम्पनी या नगर निगम के कर एवं राजस्व अनुभाग द्वारा मांग जारी होने के 30 दिनों के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज)/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से नगर निगम द्वारा अधिकृत संस्था/कम्पनी या नगर निगम के कर एवं राजस्व अनुभाग द्वारा विलम्ब भुगतान/प्रभार लगाया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क(यूजर चार्ज)/प्रभार का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं से बकाये शुल्क की वसूली भू-राजस्व की भाँति नगर निगम के कर एवं राजस्व अनुभाग द्वारा की जायेगी।

अनुसूची-2
जुर्माना/दंड

क्र स	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक् करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना	आवासीय बल्क जन्रेटर	100 500
			5000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल पार्टी लान प्रदर्शनी और मेले स्थल	10000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लब सिनेमाघर पब्स सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य	5000
			ऐसे स्थान 5000मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	500
			फिस,मीट विक्रेता द्वारा कूड़े को पृथक्करण तरीके से न रखना	800
2	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	1.सड़क/गली में कूड़ा फेंकना, थूकना 2.नहाना, पैशाब करना जनवरो को चारा खिलाना, कपड़े धोना वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना	उत्थनकर्ता	200 से 5000 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना, एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी। 500
2	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय गैर-आवासीय/बल्क जन्रेटर	100 500

3	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	500
			गैर-आवासीय/बल्क जन्रेटर	5000
4	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट)	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000 से 20000
5	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या योजना सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	10,000
6	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूड़ादान न रखने एवं कूड़े को पृथक्करण न करने, अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200
7	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) 15(छ)	सार्वजनिक स्थलों सड़कों गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/ अन्य जानवरों द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500

निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा				
8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे के निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर. डब्ल्यू.ए	5000
			बजार एसोसिएशन, संघ	10,000
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	5000
			संस्थान	10000
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	10000
			रेस्टोरेंट	5000
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी	50000
12	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कंपनी	25000

13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15(ड)	नियमों के उपाय करने भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी या मॉकर्ट कॉम्प्लेक्स आदि	25000
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों पहाड़ियों सार्वजनिक स्थलों में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिंक कैन, टैट्टा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट का फेंकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक/वाहन/चालक	500
15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर निगम की उप विधि का होटल/अतिथिगृह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल/अतिथिगृह स्वामी	500
16		सार्वजनिक सभाओं जलूस प्रदर्शनों, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियाँ, वाणिज्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000

चन्द्र सिंह मर्तोलिया,
नगर आयुक्त,
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।